तापमान
अधिकतम 30.2 डिग्री
न्यूनतम 17.6 डिग्री

हरिभूमि
महासमुंद भूमि
रायपुर, बुधवार 25 फरवरी 2026

सरायपाली | बसना | पिथौरा | बागबाहरा | तुमगांव | खरियार रोड

10 एसडीएम ने कहा: बच्चों को बचपन से ही अपनी...

10 कन्या कॉलेज में राष्ट्रीय स्तर के संकाय विकास ...

अंतर राशि देने का फैसला लेकिन, दिन-तिथि तय नहीं, किसानों में असमंजस

हरिभूमि न्यूज ▶▶| महासमुंद

राज्य शासन द्वारा किसानों को धान की अंतर राशि होली के पूर्व देने का फैसला लिया है। लेकिन, दिन तिथि तय नहीं होने से किसानों में असमंजस है। एक ओर होली का पर्व गिनती के दिन ही शेष बचे हैं, ऐसे में किसानों को त्योहरी खर्च के लिए पैसा आने का बेसब्री से इंतजार है। वर्तमान में रबी फसल, घरेलू खर्च व त्योहार को लेकर किसानों की भीड़ जिला सहकारी बैंक में लग रही है। अंतर की राशि आने के बाद एकाएक भीड़ बढ़ने की संभावना है। राज्य शासन द्वारा खरीफ सीजन 2025-26 के लिए किसानों से 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी 3100 रुपए में की गई थी। 15 नवंबर से 31 जनवरी तक सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों ने अपना उपार्जन बेचा था। खरीदी के समय एमसपी की राशि मोटा व सरना 2369 एवं पतला 2389 रुपए प्रति क्विंटल की दर से किसानों को भुगतान किया गया था। किंतु, अंतर की राशि क्रमशः 731 एवं पतला 711 रुपए का भुगतान अभी बाकी है। जिला सहकारी बैंक पहुंचे किसानों का कहना है कि रबी फसल के लिए दवा, खाद, घरेलू व त्योहारी खर्च के लिए राशि निकालने पहुंचे हैं।

सरकार द्वारा होली के पूर्व अंतर की राशि देने का निर्णय लिया गया है। लेकिन, दिन तिथि तय नहीं की गई है। राशि आएगी तो बैंक में एकाएक भीड़ बढ़ेगी। इसके पूर्व हम अपने बचत खाते से ही राशि आहरण के लिए आए हैं।

गिनती के दिन ही बचे हैं होली का पर्व, बैंक में रोज लग रही किसानों की भीड़

सहकारी बैंक में लंबी लाइन

जिला सहकारी बैंक में एटीएम की सुविधा दी गई है। किंतु, अधिकांश किसान एटीएम का उपयोग ही नहीं करते। वहीं बैंक द्वारा मोबाइल एटीएम वैन संचालित हैं, जो कि ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में बैंकिंग सुविधाएं घर-घर पहुंचाती है। किंतु, वर्तमान में यह मोबाइल एटीएम वैन गांवों तक नहीं पहुंच पा रही है। ज्यादातर यह वैन बैंक परिसर में खड़ी नजर आती है।

लगा होलाष्टक, 4 को मनाई जाएगी होली : बता दे कि 24 फरवरी से होलाष्टक की शुरुआत हो चुकी है। आगामी 3 मार्च को होलिका दहन और 4 मार्च को रंग गुलाल खेला जाएगा।

अव्यवस्था व तकनीकी कारण बनी समस्या

जानकारी के अनुसार जिले में इस वर्ष कुल 1, 60, 118 किसानों ने धान बेचने के लिए पंजीयन कराया था। 1, 49, 567 किसानों से अब तक 10 लाख 14 हजार लाख क्विंटल से अधिक धान की खरीदी की जा चुकी है। 15 नवंबर से 31 जनवरी तक धान खरीदी की गई। इसके अलावा दो दिन और 5 व 6 फरवरी को धान खरीदी का समय दिया गया था। इसके बावजूद लगभग 10, 551 किसान धान बेचने से वंचित रह गए हैं। इस वर्ष धान खरीदी केंद्रों पर अव्यवस्था और तकनीकी कारणों से कई किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा।

खबर संक्षेप

देशी प्लेन शराब बेच रहे दो लोगों पर कार्रवाई

महासमुंद। बाइक में शराब रखकर बिक्री कर रहे दो लोगों के खिलाफ तेंदूकोना पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस को सूचना मिली थी कि दो व्य क्ति काला हरा रंग हीरो एचएफ डिलक्स मोटर सायकल क्रमांक सीजी 06 जीपी 2568 में शराब रखकर बिक्री करने हेतु ग्राम कौंसरा की ओर जा रहे हैं। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने आरोपी मेन कुमार चंद्राकर पिता टेकराम चंद्राकर (40 वर्ष)कौंसरा तथा भुनेश्वर दीवान पिता नाथूराम दीवान (42 वर्ष) कौंसरा को पकड़ा। आरोपियों के संयुक्त कब्जे से 80 पौवा देशी प्लेजन शराब (यूनिक) कीमत करीबन 6400 रुपए, मोटर साइकिल कीमत करीबन 20000 रुपए, दो मोबाईल कीमत 10000 रुपए कुल 36400 रुपए को जब्त किया गया। मामले में आरोपियों के विरूद्ध धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई।

शराब पीने की सुविधा देने वाली दो पर कार्रवाई

महासमुंद। शराब पीने-पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराने के आरोप में बागबाहरा पुलिस ने दो महिलाओं के विरूद्ध कार्रवाई की है। पुलिस ने बताया कि सूचना मिली थी कि आरोपी पम्मी बांधे अपने मकान के सामने ग्राम हरनादादर मे आने जाने वाले लोगों को शराब पीने पिलाने की सुविधा उपलब्ध करा रही है। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने आरोपी से पूछताछ की जिसपर उसने अपना नाम पम्मी बांधे पति खिलेश्वर बांधे (27 साल) हरनादादर होना बताया। इसी तरह ग्राम की एक अन्य महिला भगवती डहरिया पति रमेश डहरिया (55 साल) हरनादादर भी लोगों को शराब पीने पिलाने की सुविधा उपलब्ध करा रही थी।

नयापारा में मारपीट, आरोपियों के खिलाफ जुर्म दर्ज

महासमुंद। नगर के नयापारा में विवाह कार्यक्रम के दौरान मारपीट के मामले में कोतवाली पुलिस ने आरोपियों के विरूद्ध जुर्म दर्ज कर विवेचना में लिया है। पुलिस प्रार्थी वार्ड 11 नयापारा दलदली रोड निवासी हीरालाल मेहर ने बताया क 22 फरवरी को उसके घर में साली का विवाह कार्यक्रम था, बारातियों के विदा होने के बाद रात्रि लगभग 8-9 बजे मोहल्ले का विक्की ठाकुर, सन्नी ठाकुर, राजा ठाकुर एवं अन्य अपने साथियो के साथ आया और गाली गलौज करते हुए वहां पर बैठे मेहमानों के साथ मारपीट करने लगा। इस दौरान सन्नी ठाकुर ने प्रार्थी के साथ डंडे से मारपीट की। वहीं मारपीट से पिंटू मिरी को सिर में, सोनबती रौतिया को जांघ व अन्य जगह, रवि अजगले के सिर व शरीर के अन्य भागों में तथा गोपाल अजगले के पैर व शरीर में चोटे आई है। रवि अजगले और गोपाल अजगले ईलाज हेतु निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपियों द्वारा घर में शादी के समय लाए हुए किराया भंडार के सामान एवं साउंड सिस्टम को भी क्षतिग्रस्त किया गया।

कुर्मी समाज उपक्षेत्र बेमचा का वार्षिक अधिवेशन एक को

महासमुंद। चंद्रनाहू क्षत्रिय कुर्मी समाज उपक्षेत्र-बेमचा का वार्षिक अधिवेशन एक मार्च को प्रातः 11 बजे प्राथमिक शाला परिसर ग्राम कौंदकेरा में कार्यक्रम रखा गया है। इस अवसर पर उपक्षेत्र-बेमचा के सभी पदाधिकारियों एवं समाज के समस्त सदस्यगणों की उपस्थिति की अपील की है। उपक्षेत्र बेमचा में 11 गांव के सभी सदस्यों को निर्देशित किया गया है कि गांव के जिन प्रतिभावान छात्र-छात्राओं, महिलाओं एवं व्यक्तियों का सम्मान किया जाना है, उनकी सूची दिनांक 25 फरवरी तक अनिवार्य रूप से सचिव के पास जमा करें, ताकि उन्हें सम्मानित किया जा सके। उक्त जानकारी देवदत्त चंद्राकर अध्यक्ष चंद्रनाहू क्षत्रिय कुर्मी समाज उपक्षेत्र बेमचा, हेमेंद्र हेमू चंद्राकर सचिव ने दी है।

प्रतिक्रिया : सरकार ने गिनाईं उपलब्धियां, विपक्ष ने उठाए सवाल, पक्ष-विपक्ष आमने-सामने

विकास का बजट या चुनावी रणनीति, जिले में भी छत्तीसगढ़ बजट पर सियासत गरमाई

हरिभूमि न्यूज ▶▶| महासमुंद

- छग में प्रस्तुत बजट को लेकर राजनीतिक सरगर्मी शुरू

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट को लेकर पूरे प्रदेश के साथ-साथ जिले में भी राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। एक ओर भाजपा इसे विकास और जनहितकारी बजट बताते हुए उपलब्धियों का बखान कर रही है, वहीं कांग्रेस ने इसे अधूरा और जमीनी हकीकत से दूर बताते हुए कई सवाल खड़े किए हैं। बजट को लेकर जिले में भी पक्ष-विपक्ष के बीच बयानबाजी सामने आई हैं। बजट पेश होने के बाद दोनों दलों के नेताओं द्वारा बैठकों और चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। सोशल मीडिया से लेकर स्थानीय सभाओं तक बजट को लेकर बहस जारी है।

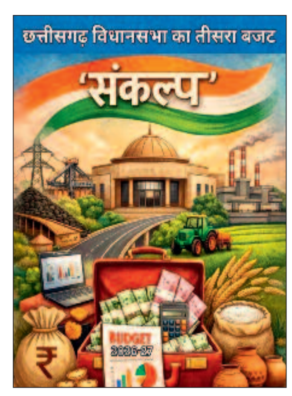

महासमुंद को क्या मिलेगा

बजट के प्रावधानों के अनुसार महासमुंद जिले को अप्रत्यक्ष रूप से कई क्षेत्रों में लाभ मिलने की उम्मीद है। जिसमें ग्रामीण सड़कों और कनेक्टिविटी में सुधार, शिक्षा संस्थानों और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, कृषि क्षेत्र में योजनाओं का लाभ एवं युवाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रम शामिल हैं। हालांकि, इन योजनाओं का वास्तविक प्रभाव आने वाले समय में उनके क्रियान्वयन पर निर्भर करेगा।

क्या कहती है जनता

फिलहाल बजट को लेकर दावे और आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है। लेकिन आम जनता की नजर इस बात पर टिकी है कि बजट की घोषणाएं जमीन पर कितनी उतरती हैं और महासमुंद जिले को इसका वास्तविक लाभ कब तक मिल पाता है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि बजट में किए गए वादों का असर तभी दिखेगा जब योजनाएं समय पर और पारदर्शिता के साथ लागू होंगी।

भाजपा का पक्षः विकास और जनहित पर जोर

भाजपा नेताओं सांसद रुपकुमारी चौधरी, भाजपा जिलाध्यक्ष एतराम साहू, महासमुंद विधायक योगेश्वर राजू सिंहा, बसना विधायक डॉ. संपत अग्रवाल, भाजपा कोषाध्यक्ष राहुल चंद्राकर, सांसद प्रतिनिधि मनमीत छाबड़ा, भाजयुमो जिलाध्यक्ष अमन वर्मा, अलका नरेश चंद्राकर, मीडिया प्रभारी आनंद साहू सहित कार्यकर्ताओं ने बजट को प्रदेश के विकास की दिशा में बड़ा कदम बताया है। उनका कहना है कि इस बजट में किसानों, महिलाओं, युवाओं और गरीब वर्ग के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। जिले के भाजपा पदाधिकारियों के अनुसार बजट में ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क और अधोसंरचना विकास को प्राथमिकता दी गई है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए पर्याप्त राशि का प्रावधान है। किसानों के लिए योजनाओं से महासमुंद जैसे कृषि प्रधान जिले को सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने इसे "संतुलित और दूरदर्शी बजट" करार दिया।

कृषि प्रधान जिले के लिए मना जा रहा संभावनाओं से भरा बजट

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट में ग्रामीण विकास, कृषि, अधोसंरचना, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों पर विशेष जोर दिया गया है। कृषि प्रधान जिले महासमुंद के लिए यह बजट संभावनाओं से भरा माना जा रहा है। विशेषकर किसानों के लिए योजनाएं, ग्रामीण सड़कों का विस्तार, सिंचाई सुविधाओं में सुधार और कौशल विकास कार्यक्रम जिले के युवाओं के लिए लाभकारी साबित हो सकते हैं।

कांग्रेस का पक्षः दिखावटी और चुनावी बताया

कांग्रेस नेता जिलाध्यक्ष द्वारिकाधीश यादव, पूर्व संसदीय सचिव एवं पूर्व विधायक विनोद चंद्राकर, पूर्व जिलाध्यक्ष रश्मि चंद्राकर, पर्यटन मंडल के पूर्व सदस्य अंकित बागबाहरा की मानें तो बजट जमीनी हकीकत से दूर है। उन्होंने इसे "दिखावटी और चुनावी" बताते हुए इसकी आलोचना की है। उनका कहना है कि बजट में बड़े-बड़े दावे तो किए गए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर इनका असर नजर नहीं आता। इनकी मानें तो बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों पर ठोस प्रावधान नहीं किए गए। किसानों और मजदूरों के लिए घोषणाएं पर्याप्त नहीं हैं। कई योजनाएं सिर्फ कागजों तक सीमित रह सकती हैं। उन्होंने कहा कि महासमुंद जिले में भी विकास कार्यों की गति अपेक्षाकृत धीमी है।

राशन भंडारण में लापरवाही पर बिखरे कलेक्टर कहा- एसडीएम करें निगरानी

हरिभूमि न्यूज ▶▶| महासमुंद

- हरिभूमि में समाचार प्रकाशन के बाद जिला प्रशासन ने लिया संज्ञान

जिले के राशन दुकानों में ई-केवायसी के नाम उपभोक्ताओं का राशन कटने और नियमित राशन भंडारण नहीं का मामला मंगलवार खाद्यान्न का वितरण नहीं हुआ है, उस पर कलेक्टर ने नाराजगी जताते हुए समय पर भंडारण एवं वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए तथा संबंधित एसडीएम को व्यक्तिगत रूप से निगरानी करने एवं नियमित निरीक्षण करने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि राशन दुकानों में प्रतिमाह चावल उत्सव अनिवार्य रूप से आयोजित करें।

ई-केवायसी के नाम पर काट दिए गए राशन, दाने-दाने को तरस रहे उपभोक्ता

को जिला कलेक्टोरेट में आयोजित समय सीमा की बैठक में छाया रहा। बैठक में कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने नाराजगी जाहिर करते हुए विभागीय अधिकारियों को व्यवस्था सुधार करने और सभी एसडीएम को व्यक्तिगत रूप से राशन दुकानों को जायजा लेने की हिदायत दी।

शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में राशन भंडारण को लेकर हरिभूमि ने 22 फरवरी को प्रमुखता से समाचार प्रकाशित किया था। इसके बाद मंगलवार को जिला कलेक्टोरेट में समय सीमा की बैठक में जिन राशन दुकानों में अब तक

बता दें कि जिले के अधिकांश राशन दुकानों में नियमित रूप से राशन भंडारण नहीं हो पा रहा है। जिसके चलते दुकान संचालक (सेल्समैन) को राशन वितरण करने में परेशानी हो रही है। कई जगह विवाद की स्थिति निर्मित हो रही है। दुकानों में कभी चावल पहुंच रहा तो कभी शक्कर गायब है। तो कभी नमक और अन्य सामग्री नियमित रूप से नहीं पहुंच पा रही है। आगामी होली का पर्व है, ऐसे में सभी हितग्राहियों को राशन वितरण करना है। लेकिन, सामग्री के अभाव में सेल्समैनों की मुश्किलें बढ़ गई है।

कलेक्टर ने जन चौपाल में सुनी लोगों की समस्याएं

- आवेदनों के शीघ्र निराकरण के संबंधितों को दिए निर्देश

महासमुंद। कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने जिला कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में आयोजित जन चौपाल में जिले के जनसामान्य की समस्याएं सुनी। कलेक्टर लंगेह ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को प्राप्त सभी आवेदनों को प्राथमिकता के साथ शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही आवेदनों का अवलोकन कर नियमानुसार पात्र हितग्राहियों को शासकीय योजनाओं से लाभान्वित करने कहा। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को उनके विभाग से संबंधित आवेदन प्रदान कर शीघ्र निराकरण करने के लिए निर्देशित किया। जन चौपाल में कुल 72 आवेदन प्राप्त हुए। जन चौपाल में ग्राम पंचायत नर्रा के शेख फरीद ने पेयजल की समस्या के निराकरण के लिए नलकूप खनन हेतु आवेदन दिए। इसी तरह ग्राम तेंदूकोना निवासी कमला साहू ने आकस्मिक मृत्यु होने पर नियम के तहत मुआवजा राशि के संबंध में, ग्राम मुढ़ेना निवासी हेमलाल सिंह ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना का लाभ दिलाने, वार्ड भानपुर बागबाहरा निवासी संजय ध्रुव ने निजी जमीन पर अवैध अतिक्रमण कर निर्माण पर रोक लगाने हेतु, ग्राम लभरा खुर्द महासमुंद निवासी बलराम सेन ने श्रमिक पंजीयन कार्ड में संशोधन हेतु, ग्राम पंचायत बम्हनी के ग्रामवासियों ने अवैध शराब बिक्री पर रोक लगाने हेत, ग्राम कोसरंगी निवासी डोमन लाल साहू ने किसान सम्मान निधि की राशि दिलाने हेतु, ग्राम चोरभट्टी निवासी दिनेश यादव ने आकस्मिक मृत्यु होने पर आर्थिक सहायता राशि प्राप्त के लिए एवं ग्राम घोड़ारी निवासी फनिया ठाकुर ने शौचालय एवं गैस कनेक्शन प्रदाय करने हेतु आवेदन किए। इस अवसर पर जिपं सीईओ हेमंत नंदनवार आदि उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री के आश्वासन के 5 माह बाद भी एनएचएम कर्मचारियों की 6 मांगें अधूरी

हरिभूमि न्यूज ▶▶| महासमुंद

- प्रशासनिक लेटलतीफी के कारण कर्मचारियों में बढ़ रहा रोष, 17 हजार से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मचारी विधानसभा घेराव की तैयारी

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के कर्मचारी एक बार फिर अपनी लंबित मांगों को लेकर लामबंद हो गए हैं। आगामी विधानसभा सत्र के दौरान एनएचएम कर्मचारियों की वर्षों से लंबित मांगों को प्रमुखता से उठाया जाएगा तथा मांगों के निराकरण हेतु घेराव एवं आंदोलन की तैयारी की जा रही है। ज्ञात हो कि एनएचएम कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में ग्रेड पे प्रदान करना, चिकित्सा परिचर्या सुविधा उपलब्ध कराना, अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान, स्थानांतरण नीति लागू करना, नई मानव संसाधन नीति लागू करना तथा नियमित कर्मचारियों की भांति वेतन खाते के माध्यम से बीमा सुविधा प्रदान करना शामिल है। इन मांगों से संबंधित फाइलें मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री द्वारा आश्वासन दिए जाने के बावजूद पिछले 5 माह से प्रशासनिक स्तर पर लंबित पड़ी हैं। संघ के पदाधिकारियों द्वारा कई बार संबंधित अधिकारियों एवं स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात कर मांगों के शीघ्र निराकरण का आग्रह किया गया तथा मंत्री द्वारा सार्वजनिक घोषणा भी की गई, किंतु आज तक कोई ठोस आदेश जारी नहीं किया गया है। इससे प्रदेश के एनएचएम कर्मचारियों में भारी असंतोष एवं रोष व्याप्त है। एनएचएम कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अमित मिरी, प्रदेश संरक्षक हेमंत सिन्हा एवं प्रदेश प्रवक्ता पुरन दास ने संयुक्त रूप से बयान जारी कर कहा कि मंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन के बावजूद फाइलों में कोई प्रगति नहीं हो रही है। यदि शीघ्र ही कर्मचारियों की लंबित मांगों का निराकरण नहीं किया गया, तो प्रदेश के लगभग 17, 500 एनएचएम स्वास्थ्य कर्मचारी व्यापक आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन एवं प्रशासन की होगी। संघ ने शासन एवं प्रशासन से मांग की है कि कर्मचारियों की लंबित मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लिया जाए, ताकि स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों को न्याय मिल सके एवं प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं सुचारू रूप से संचालित होती रहें। उक्त जानकारी महासमुंद जिलाध्यक्ष राम गोपाल खूंटे ने दी है।

मौसम के बदलाव के चलते अस्पताल में भी लगातार बढ़ रही मरीजों की संख्या

दिनभर छाए रहे बादल, हल्की बूंदा-बांदी ने बढ़ाई परेशानी

हरिभूमि न्यूज ▶▶| महासमुंद

सोमवार और मंगलवार को सुबह से ही क्षेत्र में बादल छाए रहे। वहीं प्रदेश के कई हिस्सों में जोरदार बारिश भी हुई। शहर तथा आसपास के इलाकों में बूंदा बांदी के साथ देर शाम शहर के भी कुछ इलाकों में हल्की बारिश हुई। मौसम में इस प्रकार का अप्रत्याशित बदलाव देखने को मिला। इसके चलते जहां परिवहन होना शेष धान को लेकर समितियों की चिंता बढ़ा दी वहीं मौसम के बदलाव के कारण अस्पताल में भी मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है।

बता दें कि 15 जनवरी को सूर्य के उत्तरायण होने के साथ ही मौसम में लगातार बदलाव होना

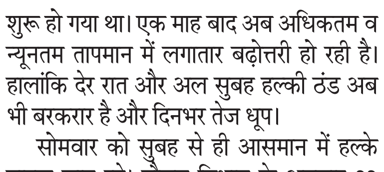

शुरू हो गया था। एक माह बाद अब अधिकतम व न्यूनतम तापमान में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है। हालांकि देर रात और अल सुबह हल्की ठंड अब भी बरकरार है और दिनभर तेज धूप।

सोमवार को सुबह से ही आसमान में हल्के बादल छाए रहे। मौसम विभाग के अनुसार 22 फरवरी की दोपहर से ही दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना सुस्पष्ट निम्न दबाव बना हुआ है। इससे संबंधित चक्रवाती परिसंचरण समुद्र तल से 5.8 किमी ऊपर तक फैला हुआ था। संभावना है कि यह प्रारंभ में पश्चिम-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ेगा और फिर अगले 48 घंटों के दौरान धीरे-धीरे दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर उत्तर-पूर्व की ओर मुड़ जाएगा। वहीं दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने सुस्पष्ट निम्न दबाव क्षेत्र से लेकर मध्य तमिलनाडु और आंतरिक कर्नाटक से होते हुए मध्य महाराष्ट्र तक समुद्र तल से 0.9 किमी ऊपर स्थित द्रोणिका बनी हुई है) मध्य क्षोभमंडलीय पछुआ हवाओं में बनी द्रोणिका का अक्ष समुद्र तल से 5.8 किमी ऊपर लगभग 93 पूर्व देशांतर के अनुदिश और अक्षांश 24 उत्तर के उत्तर में स्थित है।

कैसा रहेगा आगामी दिनों में मौसम का मिजाज

मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में लगातार बढ़ोत्तरी होगी। आज दोपहर 12 बजे तक अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहा। जबकि सप्ताह अंत यह 2 डिग्री और बढ़ने की संभावना है। मौसम में हो रही तब्दीली के चलते लोगों के स्वास्थ्य पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। सुबह और रात में ठंड दिनभर कड़ी धूप से लोग बीमार हो रहे हैं। जिसमें सर्दी, खसी और बुखार के मरीज अधिक हैं।

प्रधानमंत्री का पुतला दहन कर युवा कांग्रेस ने जताया जोरदार विरोध, पुलिस से हुई खींचातानी

बागबाहरा। नगर में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा अशोक होटल चौक के सामने प्रधानमंत्री का पुतला दहन कर जोरदार प्रदर्शन किया गया। यह विरोध प्रदर्शन युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब की गिरफ्तारी के विरोध में आयोजित किया गया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और गिरफ्तारी को राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित बताते हुए तत्काल रिहाई की मांग की। युवा कांग्रेस नेताओं ने कहा कि देश में लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करने तथा विपक्ष की आवाज दबाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही राष्ट्रीय अध्यक्ष को रिहा नहीं किया गया तो आंदोलन को और उग्र रूप दिया जाएगा। इस दौरान पुतला दहन को लेकर पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच खींचातानी की स्थिति भी निर्मित हो गई। कार्यक्रम में वरिष्ठ कांग्रेस नेता लखबीर छाबड़ा, ताम्रध्वज बघेल सहित लोकेश उइके, पोखराज साहू, देवेश साहू, आदि बोकड़े, खोमेश साहू, अभिषेक यादव, उत्तम राणा, दुर्गेश यादव, राजू यादव, राजा कोहली, कृष्णा यादव, हितेश खरे, प्रतीक चंद्राकर, रोहित सोनवानी आदि उपस्थित रहे।

पोर्टल में तकनीकी खामी, डॉयवर्सन के लिए ऑनलाइन आवेदन में दिक्कत

हरिभूमि न्यूज ▶▶| रायपुर

छत्तीसगढ़ में जमीन का डॉयवर्सन कराने की प्रक्रिया को सरल और सुविधाजनक बनाने के लिए शासन ने इसे ऑनलाइन कर दिया है। इस सुविधा के तहत जमीन का डॉयवर्सन कोई भी घर बैठे राजस्व विभाग के पोर्टल से आवेदन कर ऑनलाइन कर सकता है।

आवेदन के साथ जमीन के दस्तावेजों को भी अपलोड करना है। इस नए सिस्टम को लागू हुए दो महीने से अधिक समय बीत चुका है। इसके बाद भी पोर्टल अभी तक सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, जिसके कारण पोर्टल में ऑनलाइन आवेदन तक नहीं हो पा रहे हैं। इस वजह से डायवर्सन की प्रक्रिया भी फिलहाल ठप पड़ी हुई है। इधर राजस्व अधिकारियों का कहना है कि पोर्टल के डायवर्सन साफ्टवेयर में कुछ तकनीकी खराबी है, जिसके कारण आवेदन भी नहीं आ रहे हैं। यह खराबी सुधरते ही ऑनलाइन डायवर्सन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी, जिससे लोगों को तहसील कार्यालय आने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी।

खास खबर

पुराने लंबित आवेदनों का ही निराकरण

तहसील कार्यालयों में ऑनलाइन सिस्टम लागू होने की तारीख से पहले डायवर्सन के लिए ऑफलाइन किए गए आवेदनों का ही निराकरण किया जा रहा है। हालांकि इनमें भी कई आवेदन ऐसे हैं, जो पिछले कई महीनों से लंबित हैं, जिनका निराकरण किया जाना है।

प्रदेश में दिसंबर 2025 से लागू है डॉयवर्सन का ऑनलाइन सिस्टम, ऑफलाइन सुविधा बंद

फाइल फोटो

पोर्टल में कुछ दिक्कत बताई जा रही

पोर्टल में कुछ दिक्कत बताई जा रही है। अभी तक डायवर्सन के लिए एक भी ऑनलाइन आवेदन नहीं आया है। आवेदन आने पर 15 दिनों के भीतर उसका निराकरण किया जाएगा।

- नंदकुमार चौबे, एसडीएम रायपुर

लोग लगा रहे तहसील कार्यालय के चक्कर

पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन नहीं होने के कारण पिछले दो माह से डायवर्सन कराने वाले लोग तहसील कार्यालयों के चक्कर भी काट रहे हैं। रायपुर तहसील कार्यालय में हर दिन दो से तीन लोग जमीन के दस्तावेजों के साथ आवेदन लेकर पहुंच रहे हैं, लेकिन ऑफलाइन आवेदन लेने की प्रक्रिया बंद होने के कारण उन्हें बैरंग लौटया जा रहा है।

रायपुर जिले में एक भी आवेदन नहीं

डायवर्सन की प्रक्रिया जब से ऑनलाइन हुआ है, तब से लेकर अभी तक रायपुर जिले में डावर्सन के लिए एक भी आवेदन पोर्टल के माध्यम से नहीं किया गया है। इसकी जानकारी तहसील कार्यालय से मिली है। तहसील कार्यालय के राजस्व अधिकारी एवं डायवर्सन शाखा के प्रभारी ने बताया कि पोर्टल में डायवर्सन के लिए अलग से ऑप्शन दिया हुआ है। इस ऑप्शन के माध्यम से ही आवेदन किया जाना है, लेकिन आवेदन करने के दौरान आवेदन सहित दस्तावेज अपलोड नहीं हो पा रहे हैं। उनका कहना है कि पोर्टल के साफ्टवेयर में कोई तकनीकी खराबी है, जिसके कारण आवेदन एवं दस्तावेज अपलोड नहीं हो पा रहे हैं। आवेदन एवं दस्तावेज अपलोड होने पर ही डायवर्सन की प्रक्रिया पूरी हो पाएगी। उन्होंने बताया कि अभी तक पोर्टल के माध्यम से एक भी आवेदन नहीं आया है।

खबर संक्षेप

राज्यसभा के लिए साहू समाज ने मांगा प्रतिनिधित्व

रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ के एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव और नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने साहू समाज के प्रतिनिधि को राज्यसभा सदस्य बनाने जाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। साथ ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज से दूरभाष पर चर्चा की गई। इस मौके पर संघ के प्रदेशाध्यक्ष निरेन्द्र साहू ने स्पष्ट रूप से कहा कि छत्तीसगढ़ के विकास की धुरी रहने वाला साहू समाज प्रदेश में बहुसंख्यक और सामाजिक रूप से सबसे अग्रणी है, इसके बावजूद आज तक राज्यसभा में समाज के किसी भी व्यक्ति को अवसर नहीं मिलना चिंता का विषय है। समाज अब चाहता है कि उसकी आवाज दिल्ली के गलियारों में भी गूंजे। मुलाकात करने वालों में प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश संयुक्त सचिव प्रदीप साहू के साथ गोपाल साहू, चूड़ामणि साहू , रोबिन साहू, देवदत्त साहू, प्रवीण साहू, गोपी साहू, लुकेश आदि उपस्थित थे।

राष्ट्र कार्य के लिए स्वस्थ मन, बुद्धि, शरीर का होना जरूरी

रायपुर। राजधानी रायपुर में सोमवार को लोकतंत्र सेनानी संघ व लोकतंत्र प्रहरी की संयुक्त बैठक हुई, जिसमें प्रदेश से 120 से अधिक सेनानियों एवं नियुक्त प्रहरी पदाधिकारियों शामिल हुए। बैठक में लोकतंत्र प्रहरी के नवनियुक्त पदाधिकारियों, संभागीय अध्यक्षों व सभी जिला अध्यक्षों को लोकतंत्र सेनानी संघ के प्रांतीय पदाधिकारियों ने नियुक्ति पत्र प्रदान कर दुपट्टा पहनाकर सम्मानित किया। इस मौके पर छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष रूपनारायण सिन्हा ने कहा कि राष्ट्र कार्य के लिए स्वस्थ शरीर, मन एवं बुद्धिमान मस्तिष्क का होना आवश्यक है। उन्होंने जोर देकर कहा कि देश की आजादी की लड़ाई हो या आपातकाल के विरुद्ध संघर्ष, इनका नेतृत्व हमेशा इन गुणों से युक्त युवा पीढ़ी ने ही किया।

मेहर समाज ने गुरु रविदास की मनाई जयंती

रायपुर। मेहर समाज द्वारा कोटा स्थित सभा भवन में रविवार को संत शिरोमणि विश्व गुरु रविदास की 649 वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर मेहर समाज महिला संगठन प्रदेश अध्यक्ष कुलेश्वरी बघेल, नरेश लदेर, जिलाध्यक्ष बसंती लहरी, विष्णु गजेन्द्र, विश्राम गजेन्द्र, शंकर लहरी, भारती मिर्झा, सोनिया तुरकाने, नंदनी मोहित रावत, गीता तुरकाने, सीता गजेन्द्र एवं बड़ी संख्या में सामाजिक नागरिक उपस्थित थे।

नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी ने किया स्थल निरीक्षण

मिनीमाता, शास्त्री चौक, कबीर चौक, भारत माता चौक में अंधेरा, निगम की व्यवस्था बेहाल

हरिभूमि न्यूज ▶▶| रायपुर

राजधानी के विभिन्न चौक में स्थापित महापुरुषों के प्रतिमा स्थल की देखरेख में नगर निगम प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। शहर के विभिन्न प्रतिमा स्थल पर पर्याप्त रोशनी नहीं होने से वहां अंधेरा छाया हुआ है। साफ-सफाई और प्रतिमा की रंगाई, धुलाई की व्यवस्था नहीं हो रही। नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी ने शहरके विभिन्न क्षेत्रों के चौक का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पाया कि छत्तीसगढ़ महतारी चौक अंधेरे में डूबा हुआ है। चौक के आसपास रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। इसी तरह भारत माता चौक जहां पहले जगमग रोशनी के चलते यह स्थल लोगों के आकर्षण का केन्द्र हुआ करता था, वहां अंधेरा छाया हुआ है।

इसी तरह कलेक्टरोट परिसर के महतारी चौक जहां नगर निगम सहित जिला प्रशासन के अधिकारी कर्मचारियों का आना-जाना लगा रहता है, उस चौक की दशा ये है कि रात में लाइट तक नहीं जल रही है। इसी तरह छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद स्वर्गीय मिनी माता के नाम से पंडरी के पुराने बस स्टेंड परिसर स्थित मिनीमाता चौक में कमोबेश यही स्थिति देखने को मिली।

महापुरुषों के प्रतिमा स्थल की बदहाली पर उठाए सवाल

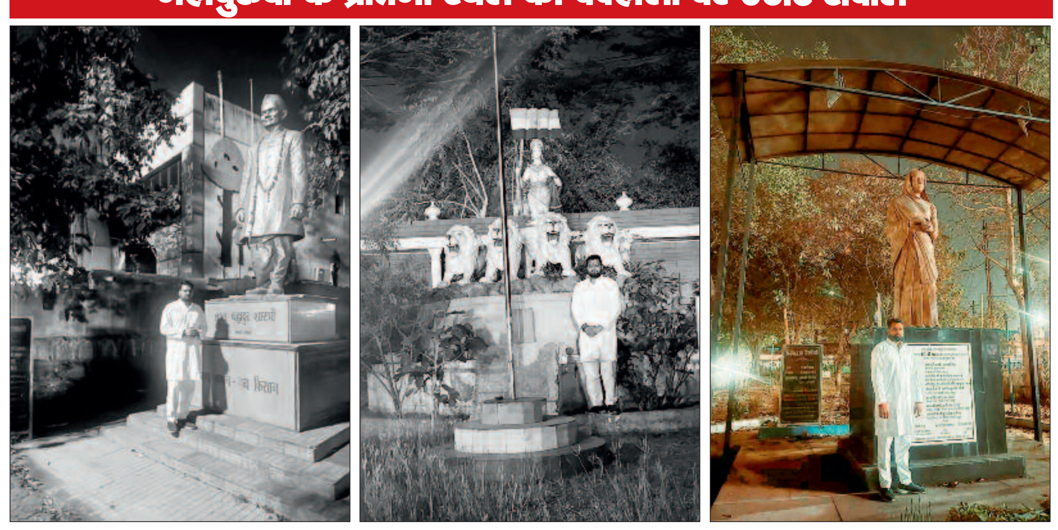

'हम ही संवारेंगे' इस जुमलेबाजी से काम नहीं चलेगा

नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी ने शहरी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि राजधानी को सुंदर शहर बनाने की परिकल्पना करने से काम नहीं चलेगा। शहर के प्रमुख चौराहों को खूबसूरत बनाने अच्छी रोशनी, स्वच्छता के साथ स्थल की देखरेख की जरूरत है। छत्तीसगढ़ के अलावा दूसरे राज्यों से आने वाले यहां के खूबसूरती की सराहना करें, तब बात बनेगी। केवल यह कहकर कि हमने बनाया है हम ही संवारेंगे इस जुमलेबाजी से काम नहीं चलेगा।

सफाई और प्रकाश व्यवस्था की कमी

सिविल लाइन स्थित संत कबीर चौक में रोशनी का अभाव देखा गया। निगम के नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी ने कचहरी चौक स्थित शास्त्री चौक का निरीक्षण किया। इस चौक में देश के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा स्थापित है, वहां सफाई और प्रकाश व्यवस्था की कमी देखने को मिली।

मेडिकल कालेजों में क्रिटिकल केयर यूनिट खोलने की योजना ठंडे बस्ते में, विशेषज्ञ भी आयुष्मान से दूर

हरिभूमि न्यूज ▶▶| रायपुर

- अभी केवल रायपुर में सुविधा, जिला अस्पताल में खोलने की जरूरत
- गंभीर स्थिति के मरीजों के उपचार में विशेषज्ञ निभाते हैं निर्णायक भूमिका

गंभीर स्थिति वाले मरीजों के उचित उपचार के लिए सभी मेडिकल कालेजों में क्रिटिकल केयर यूनिट खोलने की योजना ठंडे बस्ते में चली गई है। इतना ही नहीं, इलाज में विशेषज्ञों की भूमिका निभाने वाले क्रिटिकल केयर मेडिसिन विशेषज्ञों को भी आयुष्मान से दूर रखा गया है। आईसीयू के बेहतर प्रबंधन को देखते हुए इसका विस्तार जिला स्तर पर किए जाने की जरूरत है, मगर अभी यह केवल रायपुर के शासकीय मेडिकल कालेज में संचालित है।

विभिन्न विभागों में इलाज के दौरान अति गंभीर स्थिति में पहुंचने वाले मरीजों के इलाज की जिम्मेदारी क्रिटिकल केयर यूनिट के मेडिसिन विशेषज्ञ पूरी करते हैं। आईसीयू, ट्रामा, वेंटिलेटर की सुविधा वाले क्रिटिकल केयर यूनिट की आवश्यकता कोरोना महामारी के दौरान सबसे ज्यादा महसूस किया गया था। बाद में यह यूनिट सभी शासकीय मेडिकल कालेज में खोलने की योजना बनाई गई थी। 50-50 बेड के क्रिटिकल केयर यूनिट के लिए 23-23 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना थी। योजना कागजों से बाहर नहीं आई और यह सुविधा केवल रायपुर के शासकीय मेडिकल कालेज से संबंधित आंबेडकर अस्पताल में सीमित होकर रह गया।

सुदृढ़ होगी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली

छत्तीसगढ़ डॉक्टर्स फेडरेशन के अध्यक्ष डॉ. हीरा सिंह ने बताया कि क्रिटिकल केयर मेडिसिन तीन वर्षीय सुपर-स्पेशियलिटी प्रशिक्षण है, जो गंभीर रूप से बीमार मरीजों के उन्नत उपचार एवं निगरानी पर केंद्रित होता है। इस विशेषज्ञता में उन्नत वेंटिलेशन प्रबंधन, हेमोडायनामिक मॉनिटरिंग, सेप्सिस प्रबंधन, मल्टी-ऑर्गन डिसफंक्शन उपचार तथा सतत रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी जैसी जीवन-रक्षक तकनीकों में दक्षता प्रदान की जाती है। स्वास्थ्य सहायता योजना में इस विशेषज्ञता को औपचारिक रूप से शामिल किया जाना स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को अधिक सुदृढ़ बनाएगा। इस निर्णय से छोटे शहरों एवं जिला अस्पतालों में उन्नत आईसीयू सेवाओं का विस्तार होगा। इससे राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में भी गंभीर रोगियों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण उपचार उपलब्ध हो सकेगा और रेफरल बोझ में कमी आएगी।

स्टील उद्योग को लग सकता है लोड फैक्टर कम होने का झटका

हरिभूमि न्यूज ▶▶| रायपुर

बिजली के नए टैरिफ के साथ ही प्रदेशभर के स्टील उद्योगों को लोड फैक्टर के कम होने का तगड़ा झटका लग सकता है। छत्तीसगढ़ राज्य पॉवर कंपनी ने 2026-27 के नए टैरिफ के लिए जो याचिका लगाई है, उसमें लोड फैक्टर को फिर से 25 फीसदी से कम करके 10 फीसदी करने की मांग रखी है। ऐसा होने से स्टील उद्योग को टैरिफ में मिलने वाली छूट कम हो जाएगी। अभी छूट के कारण स्टील उद्योगों को घरेलू से भी कम दरों पर बिजली मिल जाती है। उद्योग को मिल रही सस्ती बिजली का जनसुनवाई में कांग्रेस के साथ ही छत्तीसगढ़ विद्युत सेवानिवृत्त कर्मचारी अधिकारी महासंघ ने भी विरोध किया है। ऐसे में आयोग लोड फैक्टर कम कर सकता है।

प्रदेश के स्टील उद्योग को लोड फैक्टर में पिछली सरकार में बड़ी राहत देते हुए उसकी बिजली को बहुत ज्यादा सस्ता कर दिया गया था। ऐसा होने से स्टील उद्योग को घरेलू से भी सस्ती बिजली मिल रही थी। इस सस्ती बिजली के खिलाफ पुराने अफसरों ने मोर्चा खोला था, लेकिन आयोग में जाने के बाद भी आयोग ने इनकी बात नहीं मानी थी। इसके बाद जब प्रदेश में एक बार फिर से भाजपा की सरकार बनी तो 2024-25 के टैरिफ के समय स्टील उद्योग का लोड फैक्टर कम करके 25 से 10 फीसदी कर दिया गया।

लोड फैक्टर से 25 फीसदी सस्ती बिजली

स्टील उद्योग के लिए एक लोड फैक्टर तय है। जिस प्लांट ने जितने किलोवाट का कनेक्शन लिया है, उसमें लोड के उपयोग के अनुसार उसके टैरिफ में प्रतिशत कम किया जाता है। 2021-22 में 63 से 70 प्रतिशत था। यानी 64 प्रतिशत का उपयोग करने वालों को टैरिफ में एक प्रतिशत की छूट मिली, इसी तरह से 70 फीसदी तक उपयोग करने वालों को 8 फीसदी छूट मिली। लेकिन इसके बाद इसको इसको 50 से 75 प्रतिशत करके 25 फीसदी तक छूट का प्रावधान कर दिया गया। एक साल इसको दस फीसदी किया गया लेकिन फिर से चल रहे सत्र में यह छूट 25 फीसदी हो गई है।

6.40 रुपए का टैरिफ हो जाता है 5.00 रुपए

बड़े उद्योगों का जितने मेगावाट का कनेक्शन है, उसका आसानी से ये 70 से 75 फीसदी तक उपयोग कर लेते हैं। 75 फीसदी उपयोग का मतलब यह है कि 6.40 रुपए प्रति यूनिट का टैरिफ सीधे-सीधा 25 फीसदी छूट के कारण 1.60 रुपए कम होकर 5.00 रुपए हो जाना। यही हो रहा है जिसके कारण स्टील उद्योगों को सस्ती कीमत पर बिजली मिल रही है। लेकिन अन्य शुल्क मिलाकर यह बिजली 7.21 रुपए की पड़ती है, ऐसा उद्योग चलाने वाले कहते हैं।

लोड फैक्टर से फायदा : *नियामक आयोग ने 2025-26 के टैरिफ में एक बार फिर से स्टील उद्योग का लोड फैक्टर बढ़ाकर 10 से 25 कर दिया। ऐसे में इस सत्र के लिए भी लोड फैक्टर के कारण स्टील उद्योग की चांदी हो गई है। हालांकि स्टील उद्योग से जुड़े कारोबारी इस बात को नकारते हैं कि उनको फायदा हो रहा है। इनका कहना है उनको सभी शुल्क मिलाकर बिजली सात रुपए से ज्यादा की पड़ती है। अगर इनकी बात मान ली जाए तो भी इनकी बिजली तो घरेलू बिजली से सस्ती ही हुई, क्योंकि 400 यूनिट से ज्यादा खपत करने पर 6.60 रुपए तो टैरिफ ही है। इसी के साथ एफपीपीएएस और अन्य शुल्क मिलाकर करीब आठ रुपए यूनिट बिजली पड़ती है। अगर खपत 600 यूनिट से ज्यादा होती है तो इसकी कीमत करीब 10 रुपए यूनिट तक हो जाती है। क्योंकि टैरिफ ही 8.30 रुपए है।*

तालाब के किनारे हिस्से पर कब्जा ढाबा की गंदगी से पानी भी प्रदूषित

विधानसभा रोड क्षेत्र का मामला

हरिभूमि न्यूज ▶▶| रायपुर

राजधानी रायपुर के विधानसभा रोड से लगा एक तालाब धीरे-धीरे पटता जा रहा है। इस तालाब का पानी भी पूरी तरह से प्रदूषित हो गया है। इसका बड़ा कारण इस तालाब के सामने सड़क से लगा एक ढाबा है। ढाबा संचालक ने न केवल इस तालाब के किनारे की जमीन को पाटकर यहां भवन तैयार करा लिया है, वहीं ढाबा के रसोई की सारी गंदगी भी तालाब में ही छोड़ी जा रही है, जिसके कारण तालाब का पानी भी प्रदूषित हो गया है।

गौर करने वाली बात यह है कि करीब सालभर पहले इस तालाब को पाटे जाने की कोशिश भी की गई थी, जिसकी शिकायत होने पर नगर निगम जोन-9 के अफसरों ने इसे रुकवाते हुए इस मामले में ढाबा संचालक की जमीन के दस्तावेजों की राजस्व विभाग द्वारा जांच भी कराई थी। इस जांच में कितनी जमीन अवैध पाई गई थी, इसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है।

आधी रात को मिट्टी डालकर तालाब को पाटने का किया गया था प्रयास

विधानसभा रोड पर प्रींस ढाबा के पीछे शासकीय तालाब है। यह तालाब कई दसक पुराना है। इस तालाब को करीब सालभर पहले पाटने का खेल चल रहा था। अज्ञात लोगों द्वारा आधी रात को जेसीबी मशीन के जरिए मिट्टी से इस तालाब को पाटा जा रहा था। इसकी सूचना मिलने पर सड्डू क्षेत्र के रहवासी मौके पर पहुंचकर इसका विडियो भी बनाए थे। इस विडियो के आधार पर ग्रामीणों ने नगर निगम के जोन कमिश्नर से लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर इस मामले में कार्रवाई किए जाने की मांग की थी। इस शिकायत के बाद नगर निगम ने खानापूर्ति कार्रवाई करते हुए तालाब जाने वाले रास्ता काटा था, ताकि कोई भी बड़ी वाहन यहां प्रवेश नहीं कर पाए, वहीं जिस जमीन पर ढाबा बना हुआ है, उसके जमीन के दस्तावेजों की जांच भी राजस्व विभाग द्वारा कराई गई थी। इस जांच में तालाब से लगी कितने जमीन ढाबा संचालक की है, इसका अब तक खुलासा नहीं हुआ है।

तालाब का पानी हुआ प्रदूषित

इधर ढाबा के रसोई की पूरी गंदगी तालाब में ही फेंकी जा रही है। रसोई की निकासी का रास्ता भी तालाब की ओर है, वहीं तालाब का किनारे का बड़ा हिस्से पर भी ढाबा संचालक द्वारा रसोई रूम है। इस रसोई रूम का निर्माण कार्य को देखकर पता चलता है कि इसका निर्माण तालाब के हिस्से को पाटकर बनाया गया है। फिलहाल तालाब को बचाने के लिए अभी तक नगर निगम, राजस्व विभाग और जिला प्रशासन की ओर से कोई कार्यवाही नहीं गई है।

पंचायतों का विकास भाजपा की प्राथमिकता से बाहर : सृष्टि

कार्यकाल 1 वर्ष पूर्ण होने के बाद भी पंचायतों के बैंक खाते खाली

हरिभूमि न्यूज ▶▶| महासमुंद

जिला पंचायत सदस्य सृष्टि अमर चंद्राकर ने कहा कि त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव के एक वर्ष पूर्ण होने के बाद भी पंचायतों के खाते खाली हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा की साय सरकार में पंचायतें बेहाल हो चुकी है। सरकार का जो रवैया है उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि गांवों का विकास भाजपा सरकार की प्राथमिकता से बाहर है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बने 2 वर्ष से अधिक तथा पंचायत चुनाव को एक वर्ष का समय बीत चुका है, लेकिन ग्रामीण विकास की बुनियाद कही जाने वाली पंचायतें आज इतिहास की सबसे कमजोर स्थिति में पहुंच चुकी हैं।

सृष्टि ने कहा कि सत्ता परिवर्तन के बाद सरकार ने न तो पंचायतों के लिए कोई बड़ी योजना शुरू की, और न ही पिछली सरकार के कार्यकाल की 15वें वित्त आयोग की लंबित राशि को जारी करने की कोई पहल की। नतीजा यह है कि पंचायतें सिर्फ नाम की रह गई हैं, जबकि फैसले और फंड राजधानी की फाइलों में कैद हैं। पंचायत चुनाव में चुने हुए जनप्रतिनिधि केवल नाम का रह गया है। सरपंच, पंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य केवल डमी बनकर रह चुके हैं। राशि नहीं होने से पंचायतों के विकास में जनप्रतिनिधि अपना योगदान नहीं दे पा रहे हैं। सरपंच, पंच अपने गांवों के लोगों का सामना नहीं कर पा रहे हैं। पूर्व में महासमुंद ब्लाक के पंचायत प्रतिनिधियों ने 15 वें वित्त की राशि की मांग को लेकर धरना-आंदोलन किया था, जिसके बाद साल में 4 बार किश्तों में मिलने वाली 15 वें वित्त की राशि का केवल एक किश्त पंचायतों को मिला। लेकिन, उक्त राशि का भी आहरण पर रोक लगा दी गई।

17 हजार स्वास्थ्य कर्मचारी करेंगे विधानसभा घेराव

रायपुर। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारी एक बार फिर अपनी लंबित मांगों को लेकर लामबंद हो गए हैं। मांगों के निराकरण के लिए वे घेराव एवं आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। एनएचएम कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में ग्रेड पे प्रदान करना, चिकित्सा परिचर्या सुविधा उपलब्ध कराना, अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान, स्थानांतरण नीति लागू करना, नई मानव संसाधन नीति लागू करना तथा नियमित कर्मचारियों की भांति वेतन खाते के माध्यम से बीमा सुविधा प्रदान करना शामिल है। कर्मचारी संघ का कहना है, मांग संबंधित फाइल मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री द्वारा आश्वासन दिए जाने के बाद भी पिछले 5 माह से प्रशासनिक स्तर पर लंबित पड़ी है।

पेंशन योग्य की जाए पूर्व सेवा

रायपुर। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने पेश किए जाने वाले राजकीय बजट के अंतर्गत संविलियन पूर्व सेवा को पेंशन के लिए मान्य किये जाने की उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा, दीर्घकालीन सेवाओं को अप्रासंगिक मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

धोबी समाज ने मनाई संत गाडगे की जयंती

रायपुर। धोबी समाज द्वारा बालोद जिले के आमदी पलारी में सोमवार को स्वच्छता के जनक राष्ट्रसंत गाडगेजी की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर धोबी समाज के प्रदेशाध्यक्ष सूरज निर्मलकर के अध्यक्षता में अधिवेशन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में समाज के अनेक दिग्गज नेता शामिल हुए। इसके बाद कलश यात्रा निकालकर नगर भ्रमण किया गया। इस मौके पर समाज की प्रदेशाध्यक्ष श्री निर्मलकर ने कहा, संत गाडगेजी के जीवन चरित्र से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और उनके बताए मार्ग पर चलना चाहिए। संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर ने अपने लेख में स्पष्ट लिखा कि वे संविधान का निर्माण संत बाबा गाडगे से प्रेरणा लेकर कर रहे हैं, जबकि संत बाबा गाडगेजी उतने अधिक पढ़े-लिखे नहीं थे, लेकिन शिक्षा की ओर ध्यान देने की नसीहत समाज के लोगों को दी। श्री निर्मलकर ने समाज के मुखिया से आव्हान किया कि अलग-अलग आयोजन करने के बजाय राजधानी में शानदार आयोजन करें और वह आयोजन दो दिवसीय रहे भले आयोजन अगले वर्ष हो। लेकिन समाज की ताकत दिखेगी। राजधानी के अध्यक्ष वरुण निर्मलकर ने बताया कि अधिवेशन को विधायक संगीता सिन्हा, लक्ष्मी अशोक साहू, चंद्रहास निर्मलकर आदि ने संबोधित किया।

विज्ञापन हेतु संपर्क करें : 0771-4242213, 7987119756, 9303508130

विकसित छत्तीसगढ़ बनाने का समावेशी बजट : राहुल

महासमुंद। भाजपा जिला कोषाध्यक्ष राहुल चंद्राकर ने वित्त मंत्री ओपी चौधरी द्वारा प्रस्तुत साय सरकार के तीसरे बजट को छत्तीसगढ़ के विकास का संकल्प बताते हुए कहा कि इस बजट में गांव, गरीब, किसान, मजदूर, युवा, महिलाओं के हितों को सर्वोपरि रखा है। उन्होंने कहा कि यह बजट विकास, सुशासन और आर्थिक मजबूती की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश और रोजगार सृजन पर विशेष फोकस किया गया है, जिससे राज्यों को भी प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। मोदी की गारंटी को पूरा करने बजट में विशेष प्रावधान किए गए हैं। 1.72 लाख करोड़ का विशालकाय बजट छत्तीसगढ़ के विकास को नई गति प्रदान करने वाला सिद्ध होगा। महतारी वंदन योजना के तहत प्रदेश की माताओं बहनों को आत्मनिर्भर बनाने प्रतिमाह 1 हजार की राशि दी जा रही है। जिसे निर्बाध व सुचारू रूप से आगे भी संचालित करने 8200 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

अमृत काल में विकसित छत्तीसगढ़ की नींव रखेगा यह ऐतिहासिक बजट : विधायक डॉ. संपत

हरिभूमि न्यूज ⏭ सांकरा

■ बसना विधायक डाक्टर संपत अग्रवाल ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा : छत्तीसगढ़ के सपने को साकार करने वाला ऐतिहासिक बजट

छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रस्तुत वर्ष 2026-27 के बजट पर अपनी विस्तृत प्रतिक्रिया देते हुए बसना विधायक डॉ. संपत अग्रवाल ने बजट की वैचारिक गहराई पर प्रकाश डालते हुए कहा कि विष्णुदेव साय सरकार के प्रथम वर्ष की थीम जहां 'ज्ञान' (गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी) पर आधारित थी, वहीं इस वर्ष इसे 'गति' (गुड गवर्नेंस, एक्सीलेरैटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नॉलॉजी और इंडस्ट्रियल ग्रोथ) के साथ जोड़कर 'संकल्प' की अवधारणा में पिरोया गया है। उन्होंने कहा कि यह बजट राज्य की नीति को प्रदर्शन में और निवेश को परिणामों में बदलने की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है। बजट की प्रमुख घोषणाओं और उनकी बारीकियों पर विस्तार से चर्चा करते हुए विधायक डॉ. संपत अग्रवाल ने बुनियादी ढांचे के सुदृढ़ीकरण को राज्य की प्रगति का आधार बताया। उन्होंने रेखांकित किया कि लोक निर्माण विभाग के माध्यम से प्रदेश भर में सड़कों और सरकारी भवनों का आधुनिक जाल बिछाने के उद्देश्य से 9,451 करोड़ रुपए का ऐतिहासिक बजटीय आवंटन किया गया है, जो अधोसंरचना के क्षेत्र में एक नई क्रांति लाएगा। इसी क्रम में आम नागरिक की बुनियादी जरूरतों को प्राथमिकता देते हुए उन्होंने बताया कि हर घर तक शुद्ध और सुरक्षित पेयजल पहुंचाने के संकल्प को पूरा करने के लिए 'जल जीवन मिशन' के अंतर्गत 3,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प को चरितार्थ करने वाला ऐतिहासिक बजटः रूपकुमारी

महासमुंद। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष और सांसद रूपकुमारी चौधरी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'विकसित भारत' के विजन को छत्तीसगढ़ की धरती पर उतारने वाला एक जन-हितैषी और समावेशी बजट बताया है। सांसद चौधरी ने कहा कि छत्तीसगढ़िया लोगों की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब यह बजट 'ज्ञान' की प्रगति सुनिश्चित करते हुए राज्य को विकास की 'गति' प्रदान करने के 'संकल्प' को सिद्ध करेगा। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष व सांसद चौधरी ने कहा कि हमारी सरकार ने 'रानी दुर्गावती योजना' की घोषणा कर बेटियों के भविष्य को सुरक्षित किया है। जन्म लेने वाली बच्चियों को 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 1.50 लाख रुपए की राशि प्रदान करना प्रदेश की नारी शक्ति के प्रति मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की संवेदनशीलता को दर्शाता है। साथ ही 'महतारी वंदन योजना' के तहत 70 लाख महिलाओं को निरंतर मिल रही सहायता और नई 'लखपति भ्रमण दीदी योजना' महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाएगी। चौधरी ने बजट की 'संकल्प' (समावेशी विकास, अधोसंरचना, निवेश, कुशल मानव संसाधन, अंत्योदय, लाइवलीहुड और पॉलिसी से परिणाम) थीम की सराहना करते हुए कहा कि 1.72 लाख करोड़ का यह बजट छत्तीसगढ़ को देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में खड़ा करेगा। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष व सांसद रूपकुमारी ने कहा कि प्रदेश में 23 नए औद्योगिक पार्कों की स्थापना से स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खुलेंगे। इसी प्रकार अबूझमाड़ और जगरगुंडा जैसे क्षेत्रों में 100 करोड़ रुपए की लागत से 'शिक्षा शहर' का निर्माण बस्तर के भविष्य को बदल देगा। कुनकुरी, मनेंद्रगढ़ और दंतेवाड़ा में नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना और रायपुर में आधुनिक खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला का निर्माण प्रदेश के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूती देगा। सांसद ने कहा कि बजट में बस्तर की इंद्रावती नदी पर मातवर और देउरगांव बैराजों के लिए 2,024 करोड़ का प्रावधान किसानों की सिंचाई क्षमता को बढ़ाएगा।

बजट जनाकांक्षाओं के विपरीत, 500 रुपए में रसोई गैस देने के वादे पर अमल नहीं : विनोद

महासमुंद। पूर्व संसदीय सचिव छग शासन व महासमुंद के पूर्व विधायक विधायक विनोद सेवन लाल चंद्राकर ने वित्त मंत्री ओपी चौधरी द्वारा प्रस्तुत बजट को केवल मोदी की तारीफों का पुलिंदा बताते हुए जन आकांक्षाओं के विपरीत व प्रदेश वासियों को निराश करने वाला निरूपित किया है। चंद्राकर ने कहा कि बजट में विधानसभा चुनाव के दौरान की गई घोषणाओं का जिक्र नहीं किया गया है। महिलाओं को 500 रुपए में रसोई गैस, बेरोजगार युवाओं से किए वादे को बजट में नजर अंदाज किया गया है। प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की दिशा में कोई घोषणा नहीं हुई है।

33 हजार शिक्षकों की भर्ती को लेकर भी कोई प्रावधान नहीं किया गया। युवाओं के लिए रोजगार सृजन की कोई ठोस व्यवस्था नहीं है। बीएड अभ्यर्थी और संविदा कर्मचारी हड़ताल पर हैं, परंतु बजट में उनकी समस्याओं का कोई जिक्र नहीं किया गया। प्रदेश के दैवेभो कर्मियों को नियमित करने का वादा था। कर्मचारी आशान्वित थे कि उनकी नियमितीकरण को लेकर विशेष पहल होगी। लेकिन, उन्हें भी निराश किया गया। महाविद्यालयीन छात्राओं को मासिक ट्रेवलिंग अलाउंस देने का वादा कर सरकार बनाने वाली भाजपा की साय सरकार ने तीसरे बजट में भी कोई विशेष पैकेज की घोषणा नहीं की।

बजट के माध्यम से केवल सपना दिखाया गयाः रश्मि

महासमुंद। छग के बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए महासमुंद कांग्रेस पूर्व जिला अध्यक्ष डॉ रश्मि चंद्राकर ने कहा कि बजट भाषण लंबा और बेहद निराशाजनक रहा। बीजेपी सरकार का संकल्प धरा का धरा रह जाएगा। बजट के माध्यम से केवल सपना दिखाया गया है। डॉ रश्मि चंद्राकर के अनुसार प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार किसान हैं, लेकिन प्रस्तुत बजट में किसानों के लिए कोई ठोस और भरोसेमंद प्रावधान नजर नहीं आते।

आज का बजट जुमला एक्सप्रेस की तीसरी किश्त थाः अंकित

महासमुंद। कांग्रेस पार्टी के नेता अंकित बागबाहरा ने बताया कि छत्तीसगढ़ बजट सिर्फ छलावा बजट के अलावा कुछ नही है। अगर सब कुछ 2047 में ही होना है तो अभी सभी मंत्रियों और मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। वित्त मंत्री का आज का बजट संकल्प, ज्ञान और गति के नारों के साथ प्रस्तुत किया गया बजट है, जो कि वास्तव में बिना किसी विकल्प का अधूरा संकल्प है। जनता के लिए बहुत अल्प बजट है और पूरी तरह से इसमें सिर्फ छल कपट है, ये बजट छत्तीसगढ़ माटी-महतारी के लिए भारी अज्ञानता से भरा हुआ है। जिसमें सिर्फ झूठे आंकड़ों का ज्ञान और कुर्सी का गुमान ज्यादा दिखता है और इस बजट में विज्ञापनों की गति है, पर आम आदमी की दुर्गति वाला बजट है। अंकित ने बताया कि इस बजट की असफलता का पता इस बात से ही लगाया जा सकता है कि इसमें पूंजीगत व्यय और बुनियादी संरचना में खर्च होने वाले बजट में भारी कमी आई है। साथ ही साथ 2000 करोड़ के घाटे का बजट है। जिसमें सिर्फ आंकड़ों की जादूगरी से गुमराह करने की कोशिश हुई है। साथ ही नए रोजगार, 500 रुपए के सिलेंडर, किसानों की उन्नति उनको तत्काल घर पहुंच बोनस की बातें गायब हैं।

अंतर राशि त्योहार से पहले एक साथ देने पर किसानों में हर्षः पिलेश्वर

महासमुंद। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 2026 में किसानों के धान खरीदी करने पर क्विंटल पीछे 2369 रुपए का भुगतान किया गया था, वहीं अंतर राशि 731 रुपए का भुगतान होली पर्व के पूर्व हो जाने के ऐलान को लेकर छत्तीसगढ़ के पूरे किसान खुशी का माहौल है। महासमुंद किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष पिलेश्वर पटेल ने बताया कि इस वर्ष किसानों के फसलों में कीटों के प्रकोप से कई बार कीटनाशक दवाइयों का किसानों द्वारा छिड़काव किया गया, जिससे किसानों के फसलों व जेब में बहुत प्रभाव पड़ा है। भाजपा सरकार द्वारा अंतर राशि एक साथ देने से किसानों में भारी उत्साह देखा जा रहा है व 2026-27 में 3,00,00,000 रुपए से भी अधिक का बजट सिकासेर बांध से पाइप द्वारा महासमुंद जिले में पानी लाने को भाजपा सरकार ने शामिल कर लिया है।

यह बजट छत्तीसगढ़ को समृद्ध एवं खुशहाल बनाने का संकल्प : योगेश्वर

महासमुंद। मंगलवार को छत्तीसगढ़ सरकार में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने विधानसभा में छत्तीसगढ़ सरकार का वर्ष 2026- 27 का बजट प्रस्तुत किया। पिछले वर्ष बजट का आकार एक लाख 65 हजार करोड़ रुपए था, जो इस वर्ष बढ़कर एक लाख 72 हजार करोड़ रुपए हो गया है। वर्ष 2026-27 के बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए महासमुंद के युवा विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा ने कहा कि यह बजट छत्तीसगढ़ को समृद्ध एवं खुशहाल बनाने का संकल्प है। विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा ने कहा है कि यह बजट राज्य को तेजी से विकास के पथ पर ले जाने वाला बजट है। यह नवाचार, अधोसंरचना और समावेशी विकास को प्राथमिकता देने वाला बजट है, जो राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हमारी सरकार ने कई प्रमुख घोषणाओं को पूरा करने के लिए भी बजट प्रावधान किया है। यह बजट विकसित छत्तीसगढ़ के विजन डॉक्यूमेंट-छत्तीसगढ़ अंजोर, 2047 के लक्ष्यों की पूर्ति एवं राज्य की सतत विकास यात्रा में उठाया गया एक कदम है। हमारी सरकार ने पहले बजट में ज्ञान (जीवायएएन) के उत्थान की आधारशिला रखी, वहीं दूसरे बजट में गति (जीएटीआई) की रणनीति से प्रदेश के समग्र विकास को तीव्र करने की बात कही गई थी। वर्तमान बजट संकल्प (एसएएनकेएएलपी) थीम पर आधारित है। इसका अर्थ समावेशी विकास, अधोसंरचना, निवेश, कुशल मानव संसाधन, अंत्योदय, लाईवलीहुड, पॉलिसी से परिणाम तक है।

महासमुंद जिले को मिली बजट से करोड़ों की सौगात

बजट में महासमुंद जिले से संबंधित दो बड़ी योजनाओं के लिए बजट की घोषणा की गई है। इनमें सिकासार-कोडार नहर लिंकिंग परियोजना के लिए 3,047 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। इसके अतिरिक्त महानदी पर मोहमेला-सिरपुर बैराज निर्माण के लिए 690 करोड़ की स्वीकृति भी दी गई है। इसके अलावा नर्सिंग कालेज महासमुंद की स्थापना, द्रुतगामी सड़क सम्पर्क योजना के अंतर्गत कसडोल से गरियाबंद मार्ग का निर्माण होगा, जो बागबाहरा होते हुए जाएगा। झलप-रायतुम - अचानकपुर मार्ग के लिए 15 करोड़ रुपए का प्रावधान, जोबा से पीढ़ी-सिरपुर सड़क एवं पुल निर्माण, औद्योगिक क्षेत्र बिरकोनी में औद्योगिक विकास कार्य होंगे। पर्यटन एवं संस्कृति के क्षेत्र अंतर्गत सिरपुर में ग्लोबल मेडिटेशन सेंटर, म्यूजियम, महानदी तट पर रिवर फ्रंट, जन सुविधा के विकास, वृहद सड़कों का निर्माण होगा, जिसके लिए कुल 36 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

साय सरकार का तीसरा बजट गरीब, युवा, अन्नदाता व नारी की समृद्धि को साकार करने का संकल्पः येतराम

महासमुंद। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में वित्तमंत्री ओपी चौधरी द्वारा प्रस्तुत बजट को गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी की समृद्धि, पूंजीगत व्यय बढ़कर अधोसंरचना विकास को प्रोत्साहित करने तथा राज्य के युवाओं के लिए रोजगार एवं आजीविका को बढ़ावा देने वाला बजट बताते हुए भाजपा जिलाध्यक्ष येतराम साहू ने राज्य को समृद्ध बनाने के संकल्प को सिद्ध करने वाला बजट कहा है। साहू ने कहा कि बजट में सभी वर्गों का विशेष ख्याल रखा गया है। इस बार प्रदेश का बजट का आकार 1 लाख 72 हजार करोड़ रुपए का है। पिछले दो बजट के थीम जहां गति और ज्ञान था तो इस बार के बजट का विषय 'संकल्प' रखा गया है। इस बजट में सरकार ने साफ संदेश दिया है, उनकी प्राथमिकता में किसानों का हित सर्वोपरि है। सिकासेर लिंकिंग परियोजना के लिए 3047 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। साथ ही मोहमेला सिरपुर बैराज को भी विशेष प्रोजेक्ट की प्राथमिकता में रखकर स्वीकृति प्रदान को है।

सराहनीय, जनकल्याणकारी एवं विकासोन्मुख है बजटः आनंद

महासमुंद। छत्तीसगढ़ बजट 2026-27 पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भाजपा जिला मीडिया प्रभारी आनंद साहू ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व एवं वित्त मंत्री ओपी चौधरी के कुशल मार्गदर्शन में प्रस्तुत यह बजट अत्यंत सराहनीय, जनकल्याणकारी एवं विकासोन्मुख है। उन्होंने कहा कि सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, युवाओं के रोजगार एवं अधोसंरचना विकास पर विशेष ध्यान दिया है, जो प्रदेश को विकसित छत्तीसगढ़ @2047 की दिशा में आगे बढ़ाने वाला है। आनंद ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं वित्त मंत्री ओपी चौधरी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह बजट आमजन, किसान, युवा एवं महिलाओं के हितों को समर्पित है तथा प्रदेश के संतुलित और समग्र विकास की मजबूत नींव रखता है।

छत्तीसगढ़ बजट 2026-27 स्वागत योग्य, कर्मचारियों, किसान-युवा और बेटियों के लिए ऐतिहासिकः सलूजा

झलप। झलप के भाजपा नेता शम्मी सलूजा ने बजट का स्वागत करते हुए कहा कि 1,72,000 करोड़ के इस बजट में "विकसित छत्तीसगढ़ @2047" के संकल्प को साकार करने की स्पष्ट झलक दिखाई देती है। सलूजा ने कहा कि अब शासकीय कर्मचारियों को इलाज के लिए पहले स्वयं खर्च कर बाद में रिम्बर्समेंट की जटिल प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा। बजट में कैशलेस चिकित्सा सुविधा का प्रावधान कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत है। बजट में शामिल रानी दुर्गावती योजना के तहत बालिका के 18 वर्ष पूर्ण होने पर1.50 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक निर्णय बताया। सलूजा ने विशेष रूप से क्षेत्र से जुड़े प्रावधानों का उल्लेख करते हुए कहा कि किसानों की बहुप्रतीक्षित मांग सिकासेर-कोडार लिंकिंग, झलप-रायतुम-अचानकपुर मार्ग के लिए 15 करोड़, बागबाहरा में कॉलेज भवन निर्माण, महासमुंद में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना ये घोषणाएं क्षेत्र के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होंगी।

प्रदेश के युवाओं को समृद्ध व आत्मनिर्भर बनाने वाला बजट

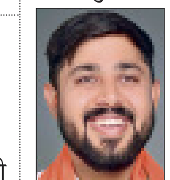

महासमुंद। भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष अमन वर्मा ने छत्तीसगढ़ सरकार के वित्त मंत्री ओपी चौधरी द्वारा प्रस्तुत बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए बजट को ऐतिहासिक तथा प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने व समृद्धि की ओर अग्रसर करने वाला बताया है। अमन ने कहा कि 1 लाख 72 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान कर प्रदेश के विकास में चहुंओर प्रगति लाने का प्रयास किया गया है। यह बजट प्रधानमंत्री के विकसित भारत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कड़ी सिद्ध होगा। बजट में युवाओं का खास ध्यान रखा गया है। "युवाओं का बजट" थीम के तहत उच्च शिक्षा, तकनीकी संस्थानों, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए बड़े वित्तीय प्रावधान किए गए हैं।

जनकल्याण और विकास को नई गति देने वाला बजटः मनमीत

महासमुंद। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रस्तुत वित्त वर्ष 2026-27 के बजट को जनहितकारी और विकासोन्मुख बताते हुए सांसद प्रतिनिधि एवं भाजपा जिला कार्यसमिति सदस्य मनमीत सिंह छाबड़ा ने इसका स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि यह बजट राज्य को समृद्ध, आत्मनिर्भर और विकसित छत्तीसगढ़ बनाने की दिशा में दूरदर्शी पहल है, जिसमें समाज के हर वर्ग के कल्याण को केंद्र में रखा गया है। छाबड़ा ने कहा कि 'संकल्प' थीम पर आधारित यह बजट केवल योजनाओं की घोषणा तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें प्रभावी रूप से धरातल पर लागू करने की स्पष्ट प्रतिबद्धता दर्शाता है। बजट में किसानों, महिलाओं, युवाओं, गरीबों और वंचित वर्गों के उत्थान को प्राथमिकता दी गई है, जिससे प्रदेश के समावेशी और संतुलित विकास को नई गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रस्तुत यह बजट राज्य की आर्थिक मजबूती का आधार बनेगा। आधारभूत संरचना के विस्तार, उद्योगों को प्रोत्साहन, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण तथा रोजगार सृजन के लिए किए गए प्रावधान प्रदेश के समग्र विकास को गति देंगे।

किसान, उद्योग, युवा, महिलाओं के लिए कल्याणकारी साबित होगा बजटः देवीचंद

महासमुंद। छग शासन के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नतृत्व में वित्त मंत्री ओपी चैधरी ने 2026 के लिए 1 लाख 72 हजार करोड़ का सर्वस्पर्शी सर्वसमावेशी ऐतिहासिक संकल्प बजट पेश करने पर नपा उपाध्यक्ष देवीचंद राठी ने कहा कि इस बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। किसान, उद्योग, युवा, महिलाओं सभी के लिए कल्याणकारी साबित होगा। क्षेत्र के सांसद रूपकुमारी चौधरी, विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा और भाजपा के क्षेत्रीय नेताओं के प्रयासों से सिकासेर कोडार नहर लिंकिंग परियोजना के लिए 3047 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दिलायी है। साथ दी महानदी पर सिरपुर बैराज के लिए 690 करोड़ की स्वीकृति बजट में कराया गया, जो महासमुन्द क्षेत्र के लिए बड़ी उपलब्धि है। सभी वर्गों को लाभ प्राप्त होगा। विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा लगातार क्षेत्र के विकास के लिए लगे रहे, जिसका यह परिणाम है कि अब तक की सबसे बड़े विकास की स्वीकृति दिलाने में कामयाब हुए हैं। राठी ने आगे बताया कि प्रदेश के युवाओं के उच्च शिक्षा में आर्थिक सहयोग के लिए 35 करोड़ प्रावधान किया गया, प्रदेश की बेटियों को 18 साल होने पर डेढ़ लाख देने की घोषणा से महिला सशक्तिकरण को ताकत मिलेगी। भूमिहीन कृषकों के लिए 600 करोड़ का प्रावधान किया गया है। महासमुंद को एक नई सौगात नर्सिंग कालेज खोले जाने का प्रावधान किया गया है। 6 साल से छोटे नन्हे बच्चों के लिए 500 आंगनबाड़ी केंद्र निर्माण के लिए 42 करोड़ की स्वीकृति दी गई। मातृ शक्ति के लिए 75 करोड़ की राशि से 250 महतारी सदन बनाने की घोषणा की गई है। निश्चित ही 2047 तक विकसित छग बनने की दिशा में यह बजट मील का पत्थर साबित होगा। छग की जनता आत्मविश्वास से भरी हुई है। चारों तरफ बजट को लेकर खुशी की लहर है।

हमने बनाया हैं हम ही संवारेंगे के संकल्प का बजट : अलका

बागबाहरा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में वित्त मंत्री ओपी चौधरी द्वारा प्रस्तुत बजट छत्तीसगढ़ के विकास विकसित छत्तीसगढ़ के लिए मिल का पत्थर साबित होगा। सरकार के पिछले दो बजट के मार्गदर्शी सिद्धांत ज्ञान और गति था यह बजट संकल्प के थीम पर आधारित है, जिसे आर्थिक विस्तार सामाजिक न्याय आधारभूत संरचना निर्माण सांस्कृतिक पहचान बने समावेशी विकास क्षेत्रीय संतुलन आधारभूत संरचना मानव संसाधन अंतिम छोर के व्यक्ति के विकास पर आधारित बजट है। उक्त बातें अलका चंद्राकर स्वतंत्र निदेशक इस्पात मंत्रालय एवं गत विधानसभा प्रत्याशी ने कहीं। इस बजट में कृषक उन्नत योजना महतारी वंदन योजना, मुख्यमंत्री खाद्यान्न कल्याण योजना, ऊर्जा सब्सिडी प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएम जन मन योजना सभी के लिए आवश्यक प्रावधान किए गए हैं। कई नई योजनाएं विकसित भारत जी राम जी योजना, मुख्यमंत्री आदर्श शहर समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री दुत्रगामी ग्रामीण सड़क संपर्क योजना, स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट शाला योजना, कैशलेस चिकित्सा सुविधा रानी दुर्गावती योजना, सीजी वायु मुख्यमंत्री शिक्षा सहयोग लखपति दीदी भ्रमण योजना, मुख्यमंत्री आस्था पथ योजना, छत्तीसगढ़ युवा शक्ति दर्शन योजना, सिरपुर विकास प्राधिकरण, साइबर तहसील का गठन आदि प्रमुख है।

पीएमश्री शालाओं को उच्च गुणवत्तापूर्ण मानकों के अनुरूप तैयार करेंः कलेक्टर

महासमुंद। कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में समय-सीमा की बैठक आयोजित कर जिले में संचालित शासकीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा की। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ हेमंत नंदनवार, अपर कलेक्टर सचिन भूतड़ा, रवि कुमार साहू, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), विभागीय जिलाधिकारी, जनपद सीईओ, नगरीय निकायों के सीएमओ तथा वीसी के माध्यम से ब्लॉक स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक में कलेक्टर लंगेह ने निर्देश दिए है कि सभी अधिकारी-कर्मचारी मंगलवार और बुधवार को अनिवार्य रूप से प्रातः 10 बजे समय पर कार्यालय पहुंचे तथा आधार बेस्ड उपस्थिति प्रणाली को अनिवार्य रूप से पालन करें। उन्होंने कहा कि निर्धारित समय पर उपस्थिति में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ई-ऑफिस प्रणाली में नियमित पत्राचार करते हुए इसे व्यवहार में प्रभावी रूप से लागू करने के निर्देश दिए।

अभी हाल ही में संपन्न हुए एसआईआर कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न होने पर कलेक्टर लंगेह ने उप जिला निर्वाचन अधिकारी, बीएलओ तथा महिला एवं बाल विकास विभाग को विशेष बधाई दी। कलेक्टर ने कहा कि निर्धारित समय सीमा में बिना किसी अवरोध के कार्य पूर्ण किया जाना सराहनीय है। कलेक्टर ने समीक्षा के दौरान संपूर्णता अभियान के अंतर्गत निर्धारित सभी संकेतकों को तय समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। साथ ही मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं पर सतत निगरानी रखते हुए गुणवत्ता के साथ कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए।

बैठक में कलेक्टर ने धान उठाव की समीक्षा करते हुए प्रतिदिन लगभग 20 हजार क्विंटल धान उठाव के निर्देश दिए। संभावित बारिश को ध्यान में रखते हुए कैप कवर सुनिश्चित करने तथा जल निकासी के लिए नाली निर्माण करने के निर्देश भी संबंधित अधिकारियों को दिए गए। साथ ही धान को नमी से बचाने एवं सुरक्षित रखने हेतु नियमित निगरानी के निर्देश दिए। उन्होंने जब्त धान के संबंध में तहसीलदार को आज शाम तक पीवी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। जिला विपणन अधिकारी ने बताया कि 24 फरवरी की स्थिति में कुल 8 लाख 21 हजार 969 मीट्रिक टन धान के लिए डीओ जारी किया गया है। जिसके विरूद्ध अब तक 6 लाख 21 हजार 451 मीट्रिक टन धान का उठाव कर लिया गया है।

इसी तरह जिन राशन दुकानों में अब तक खाद्यान्न का वितरण नहीं हुआ है, उस पर कलेक्टर ने नाराजगी जताते हुए समय पर भंडारण एवं वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं तथा संबंधित एसडीएम को व्यक्तिगत रूप से निगरानी करने एवं नियमित निरीक्षण करने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि राशन दुकानों में प्रतिमाह चावल उत्सव अनिवार्य रूप से आयोजित करें। कलेक्टर ने पीएमश्री स्कूलों का 21 बिंदुओं के आधार पर निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया। उन्होंने इन विद्यालयों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रारंभ करने, लैब एवं लाइब्रेरी को सुव्यवस्थित करने तथा शिक्षकों के नियमित प्रशिक्षण सुनिश्चित करने एवं बाला कांसेप्ट पर कार्य करने के निर्देश दिए गए। इन शालाओं में निर्माण कार्यों का सतत निरीक्षण कर गुणवत्ता के साथ समय सीमा में पूर्ण करने के भी निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने कहा कि इन स्कूलों के लिए नियुक्त सभी नोडल अधिकारी अपने दायित्वों का गंभीरता से निर्वहन करें और पीएम शालाओं को उच्च गुणवत्तापूर्ण मानकों के अनुरूप विकसित करें। उन्होंने जर्जर आंगनबाड़ी केंद्रों की अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने जनपद सीईओ को निर्देशित करते हुए कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत जिन ग्राम पंचायतों में कचरा वाहनों की खरीदी हो चुकी है, वहां डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण की शुरुआत करें तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता व्यवस्था को और मजबूत बनाया जाए। पीएम सूर्य घर योजना के तहत अधिकतम पात्र परिवारों को जोड़ने का लक्ष्य रखें।

इंडो-मलेशिया टेस्ट सीरीज बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए मुरली का हुआ चयन

महासमुंद। भारतीय बॉल बैडमिंटन महासंघ के तत्वावधान में इंडो-मलेशिया टेस्ट सीरीज पुरुष एवं महिला का आयोजन मलेशिया में 27 फरवरी से 04 मार्च 2026 तक आयोजित किया गया हैं। इस प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ से चार खिलाड़ियों का भारतीय टीम में चयन हुआ है। पुरुष वर्ग में मुरली सिंह राजपुरोहित महासमुंद, बंटी चंद्रवंशी तथा महिला वर्ग में क्षमानिधि एवं लता साहू शामिल होंगे।

खबर संक्षेप

पिछड़ा वर्ग मोर्चा ग्रामीण मंडल भाजपा महासमुंद के महामंत्री बने रामेंद्र

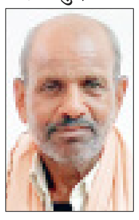

महासमुंद। ग्राम लभराकला निवासी रामेंद्र प्रकाश गिरि को पिछड़ा वर्ग मोर्चा ग्रामीण मंडल भाजपा महासमुंद के महामंत्री तथा कोसरंगी निवासी राजेंद्र गिरि को मंत्री बनाया गया है। इस पर गोस्वामी समाज महासमुंद के जिलाध्यक्ष तोषण गिरि गोस्वामी, प्रांतीय संरक्षक उमेश भारती, अशोक गिरि, नारेंद्र प्रकाश गिरि, विजय पुरी, शंकर पुरी, धीरेंद्र गिरि, ओमप्रकाश पुरी, डिगेंद्र गिरि, धर्मेंद्र गिरि, मनोज गिरि, देवेंद्र गिरि, दुर्वासा गिरि, यशवंत गिरि, पेमेंद्र गिरि, चंदन पुरी आदि पदाधिकारियों ने हर्ष जताया है।

बजट से जनता को लाभ मिलेगा, होगा राज्य का विकास : तुषार

महासमुंद। राष्ट्रीय तेली कर्मा सेना के संस्थापक व भाजपा किसान मोर्चा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अशवंत तुषार साहू ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और वित्त मंत्री ओपी चौधरी को छत्तीसगढ़ के विकास के लिए प्रस्तुत बजट 2026-27 के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया है। इस बजट में किसानों, युवाओं, महिलाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं, जो छत्तीसगढ़ के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। हम आशा करते हैं कि इस बजट के माध्यम से छत्तीसगढ़ की जनता को लाभ मिलेगा और राज्य का विकास होगा।

बजट में महतारी वंदन योजना के लिए 8200 करोड़ का प्रावधान

महासमुंद। संवेदना समूह खरोरा के सदस्य मुकेश चंद्राकर ने कहा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने मंगलवार को बजट पेश किया। बजट में महतारी वंदन योजना के लिए 8200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही कृषि उन्नत योजना के लिए बड़ी घोषणा की गई है। सरकार ने किसानों के लिए 10 हजार करोड़ रुपए की घोषणा की है। वहीं, पीएम आवास योजना ग्रामीण के लिए 4000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वन संरक्षण के लिए 913 करोड़ रुपये की घोषणा की गई है। इसके साथ ही नक्सलियों के गढ़ को एजुकेशन का हब बनाने का फैसला लिया गया है। छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय की सरकार का यह तीसरा बजट है।

कलश यात्रा 27 और शिव काली मंदिर का स्थापना दिवस 28 को

जगदलपुर। शहर की सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था मैत्री संघ द्वारा संचालित शिव काली मंदिर का 30 वां स्थापना दिवस 28 फरवरी को भव्यता के साथ मनाया जाएगा। मैत्री संघ के महासचिव सुनील साहा ने कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि स्थापना दिवस के एक दिन पूर्व 27 फरवरी को कलश यात्रा का भव्य आयोजन किया जा रहा है। कलश यात्रा दोपहर 3 बजे स्थानीय महादेव घाट से मैत्री संघ काली मंदिर तक आयोजित की जाएगी। कलश यात्रा के लिए कलश की व्यवस्था संस्था द्वारा करवाया जाएगा। स्थापना दिवस के दिन सुबह 9.30 बजे से विशेष पूजा अर्चना प्रारंभ की जाएगी एवं दोपहर 12 बजे पुष्पांजलि अर्पित होगी। उसके बाद दोपहर 2 बजे महाभंडारा का आयोजन किया जाएगा।

10 वीं के अंग्रेजी पेपर में एक भी नकल का मामला नहीं

जगदलपुर। कक्षा 10 वीं बोर्ड में आज अंग्रेजी विषय की परीक्षा में नकल का एक भी प्रकरण दर्ज नहीं हुआ। जिला शिक्षा अधिकारी बीआर बघेल ने बताया कि परीक्षा केन्द्र कुल 105 में दर्ज संख्या 8975 में 8684 उपस्थित तथा 291 अनुपस्थित रहे।

चर्चा : बागबाहरा पालिका में संपत्ति, जल समेत अन्य करों की हुई समीक्षा

बागबाहरा पालिका सख्त, टैक्स वसूली पर एक्शन मोड, बकायेदारों को नोटिस

हरिभूमि न्यूज ⏭ बागबाहरा

नगर पालिका परिषद बागबाहरा कार्यालय में सोमवार को नगर पालिकाध्यक्ष खिलेश्वरी ताम्रध्वज बघेल ने सम्पत्ति कर, जलकर और सहित अन्य करो की वसूली की समीक्षा की। सभी करों की वित्तीय वर्ष के वार्डवार वसूली की जानकारी ली गई। कम वसूली के लिए राजस्व प्रभारी को सभी बड़े बकायेदारों को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। नगर पालिका परिषद प्रशासन ने टैक्स न चुकाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्णय लिया है व उनके नाम सार्वजनिक करने के लिए आदेशित किया।

बैठक में राजस्व विभाग के अधिकारी ने बताया कि लगातार अपील के बाद प्रतिदिन 10 से 15 लोग जल कर व मकान टैक्स जमा करने पालिका आ रहे हैं। अनेक बड़े बकायेदार अभी भी टैक्स अदा करने में रुचि नहीं रहे हैं। पिछली बैठक में अध्यक्ष ने कर्मचारियों को निर्देशित किया था कि बड़े बकायादारों की सूची तैयार कर आवश्यक कार्रवाई करें। अध्यक्ष के निर्देश पर विभाग द्वारा बड़े बकायदारों की सूची तैयार कर ली गई है।

संपत्ति, जल व अन्य करों की समीक्षा, नाम सार्वजनिक करने के निर्देश

नपाध्यक्ष ने कम वसूली के लिए राजस्व प्रभारी को बड़े बकायेदारों को नोटिस जारी करने के दिए निर्देश

वार्ड 1 से 15 तक घूम रही राजस्व की टीम

नगर पालिका परिषद बागबाहरा के वार्डों से संपत्ति कर को लेकर नगर पालिका ने कई बार लोगों से अपील की कि संपत्ति कर समय पर जमा किया जाए. लेकिन नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 01 से 15 तक अधिकांश घरों में संपति कर, समेकित कर और जल शुल्क की बड़ी बकाया राशि लंबित है। नगर पालिका के अनुसार बकायादारों को पूर्व में कई बार नोटिस जारी कर कर भुगतान के लिए अवसर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद अब तक बड़ी संख्या में लोगों ने कर जमा नहीं किया है। अब नगर पालिका परिषद बागबाहरा प्रशासन ने सख्त कार्रवाई का निर्णय लिया है। नगर में लगभग 2255 घरों में पानी का कनेक्शन है। जिन पर लगभग चालू वर्ष में 29 लाख रुपया बकाया है। वहीं पिछले साल का 50 लाख की वसूली बकाया है। इसी तरह संपति कर 37 लाख व समेकित कर 39 लाख रुपए की बकाएदारी चल रही है। टैक्स जमा करने के लिए एनडीएस ऐप बनाया गया है। ऐप माध्यम से आप घर बैठे मोबाइल से अपना गृहकर-जलकर जमा कर सकते हैं।

नगर पालिका अध्यक्ष ने की अपील

नगर पालिका अध्यक्ष खिलेश्वरी ताम्रध्वज बघेल ने जनता से अपील कि है कि शहर के विकास और बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए समय पर सभी करो भुगतान बेहद आवश्यक है। होल्डिंग टैक्स घर, दुकान, प्लॉट या अन्य संपत्तियों पर लगाया जाने वाला स्थानीय कर है। इसी राशि से सड़क, नाली, सफाई, स्ट्रीट लाइट, पेयजल और पार्क जैसी आवश्यक सुविधाओं का संचालन और विकास किया जाता है। यदि नागरिक समय पर टैक्स जमा नहीं करते हैं, तो विकास कार्य प्रभावित होते हैं। नगर पालिका में राजस्व की कमी का सामना करना पड़ता है, जिससे योजनाएं अधूरी रह सकती है। समय पर भुगतान से शहर की सफाई व्यवस्था मजबूत होगी। सड़क और नाली निर्माण कार्य तेज होंगे, स्ट्रीट लाइट और पानी की सुविधा बेहतर होगी। नगर पालिका ने सभी संपत्ति धारकों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द अपना बकाया टैक्स जमा करें और शहर के विकास में भागीदार बनें।

बकायादारों को आखिरी मौका

नगर पालिका परिषद बागबाहरा के मुख्य नगरपालिका अधिकारी गिरीश कुमार चंद्रा ने बताया कि वार्ड में नगर पालिका की टीम की ड्यूटी लगाकर वसूली करवाई जा रही है। मुनादी कराकर संपत्ति, समेकित, दुकान और जल कर जमा करने को कहा जा रहा है। जमा नहीं करने वालों को चिन्हांकित कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वार्ड नंबर 1 से 15 तक वसूली अभियान चलाने के लिए नगर पालिका की राजस्व टीम का गठन किया गया।

वीडियो मेकिंग में युवराज और डिबेट कंपीटिशन में ऋतु प्रथम

हरिभूमि न्यूज ⏭ महासमुंद

शासकीय महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस-2026 द्वितीय दिवस का आयोजन उत्साहपूर्वक किया गया। इस वर्ष की थीम "वूमैन इन साइंसः कैटेलाइजिंग विकसित भारत" के अंतर्गत चार दिवसीय कार्यक्रम आयोजित है। कार्यक्रम के द्वितीय दिवस में कंप्यूटर विभाग द्वारा वीडियो मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम प्राचार्य प्रो. करुणा दुबे के मार्गदर्शन एवं मनीराम धीवर (संयोजक, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस-2026) के निर्देशन में हुआ। कार्यक्रम प्रभारी डॉ. अजय कुमार देवांगन रहे। इसमें प्रथम युवराज धीवर, द्वितीय भुनेश्वरी साहू एवं तृतीय प्रांजलि एवं वैभवी रहे। प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल में डॉ. अजय कुमार देवांगन, भूपेश पात्रा, टीकम साहू, पूजा यादव, प्रकाशमणी साहू तथा रोहिणी देवांगन सम्मिलित रहे। इसी दिन दूसरे सत्र में गणित विभाग द्वारा वूमैन इन साइंस विषय पर डिबेट कंपीटिशन का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम भी प्राचार्य प्रो. करुणा दुबे के मार्गदर्शन एवं संयोजक मनीराम धीवर के निर्देशन में हुआ। कार्यक्रम प्रभारी रुपावती रहीं। डिबेट प्रतियोगिता प्रथम ऋतु साहू, द्वितीय अंकिता विशाल, तृतीय गोपनीय साहू रहे। निर्णायक मंडल में डॉ. प्रिया बारीक, डॉ. जागृति चंद्राकर, रूपावती, रोहिणी देवांगन एवं मुकेश ढीढी उपस्थित रहे।

दानवीरों का मान-सम्मान करने से समाज में बढ़ेंगे दानदाता : कोकड़िया

संबंधित जगहों पर दानवीरों की तस्वीरें लगाई जाए

हरिभूमि न्यूज ⏭ महासमुंद

शिक्षा के मानवीयकरण के लिए चर्चित अभिभावक विद्यालय कोकड़ी सरकारी स्कूल के शिक्षक गेंदलाल कोकड़िया ने स्कूल शिक्षा विभाग, आशीबाई गोलछा स्कूल, वरिष्ठ पत्रकारों, समाज सेवकों और आशीबाई गोलछा से पढ़कर उत्तीर्ण हुए छात्रों सभी से आग्रह किया है कि आशीबाई गोलछा से संबंधित जानकारी, दस्तावेज, फोटो इंटरनेट में सार्वजनिक किया जाए। साथ ही उनकी तस्वीर, परिजनों का पता और मोबाइल नंबर भी स्कूल के बाहरी दीवार, मुख्य गेट पर भी उस महानदानी, शिक्षा के मानवीयकरण के लिए समर्पित व्यक्तित्व का फोटो लगाया जाए।

कलेक्टर, स्कूल शिक्षा मंत्री व मुख्यमंत्री, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रायपुर के संचालक ऋतुराज गंगवंशी पत्र लिखकर मांग की है कि स्कूल, तालाब, बगीचे, आम के बगीचे और किसी भी प्रकार से सार्वजनिक काम के लिए दिये गये दानवीरों की तस्वीरें संबंधित जगहों पर अनिवार्य रूप से लगाया जाए, इसे देखकर, पढ़कर, दूसरे व्यक्ति को भी मानव समाज के लिए तन-मन-धन नियोजित करने की प्रेरणा मिलती है।

एसडीएम ने कहाः बच्चों को बचपन से ही अपनी दिनचर्या व्यवस्थित कर बड़ा सपना देखना चाहिए

हरिभूमि न्यूज ⏭ बागबाहरा

पीएमश्री स्कूल शासकीय प्राथमिक शाला खोपली में वार्षिकोत्सव पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि नमिता मारकोले अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बागबाहरा द्वारा मां शारदे की छायाचित्र में पूजा अर्चना के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में विशेष अतिथि भीमसेन चंद्राकर, दिनेश चंद्राकर अध्यक्ष एसएमडीसी, अध्यक्षता प्राचार्य बीएस बंजारा ने किया। मुख्य अतिथि एवं अतिथियों का स्वागत पुष्प गुच्छ एवं बच्चों द्वारा स्वागत गीत द्वारा किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि एसडीएम मारकोले ने अपने उद्बोधन में बच्चों को बचपन से ही अपने दिनचर्या व्यवस्थित, बड़े सपने शुरू से ही देखना चाहिए। ताकि, भविष्य में आप जो बनना चाहते हैं वह प्राप्त हो जाएं जाए। इसके लिए आप पूरे लगन, ईमानदारी, पूरी निष्ठा, आत्मविश्वास, अनुशासित रहकर एवं सहनशीलता से जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। मैंने भी ग्रामीण परिवेश में रहकर शासकीय स्कूल से अपनी पढ़ाई कर आज एसडीएम जैसे सम्मानित पद पर कार्य कर रही हूं। आप भी कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, एसडीएम, तहसीलदार, वैज्ञानिक, पायलट आदि प्रतिष्ठित पदों को शिक्षा के माध्यम से प्राप्त कर सकते हो। इसके लिए आप सभी को कड़ी मेहनत, लगन से, ईमानदारी से, नियमित रूप से प्रतिदिन स्कूल में आकर पढ़ाई करने की आवश्यकता है। आज सरकार द्वारा पीएमश्री स्कूल में बहुत सारी शासकीय सुविधाएं देकर बच्चों को पढाई के लिए प्रेरित कर रही है। बहुत सारे सरकारी योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण परिवेश में रहने वाले बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए शासन सहयोग कर रही है। विद्यालय के होनहार 100 बच्चों को अलग अलग विधाओं में कापी, पेन, पेंसिल आदि देकर मुख्य अतिथि द्वारा पुरस्कार वितरण किया गया। पुरस्कार पाकर बच्चे बहुत प्रफुल्लित लग रहे थे। साथ ही साथ बच्चों ने एसडीएम के शब्दों को गंभीरता से सुना और अपने बीच पाकर गदगद हुए। इस अवसर पर पालकगण, शिक्षक शिक्षिका, बच्चे उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन शिक्षिका डिंपल वर्मा एवं क्षमता साहू ने किया। आभार प्रदर्शन प्रधान पाठक सोहद्रा देवांगन ने किया।

कन्या कॉलेज में राष्ट्रीय स्तर के संकाय विकास कार्यक्रम का शुभारंभ

हरिभूमि न्यूज ⏭ महासमुंद

शासकीय माता कर्मा कन्या महाविद्यालय द्वारा पांच दिवसीय राष्ट्रीय स्तर के संकाय विकास कार्यक्रम की शुरुआत 24 फरवरी को हाइब्रिड माध्यम (ऑनलाइन एवं ऑफलाइन) से हुई। कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षा, रोजगार एवं नेतृत्व के क्षेत्र में सभी लिंगों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना, लिंग आधारित भेदभाव एवं पूर्वाग्रहों को समाप्त करना, समान कार्य के लिए समान वेतन को प्रोत्साहित करना तथा सुरक्षित, सम्मानजनक एवं उत्पीड़न-मुक्त वातावरण का निर्माण करना है। उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि शासकीय महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय की प्राचार्य करुणा दुबे ने कहा कि छात्राओं को पुरानी सोच से आगे बढ़ते हुए जागरुकता एवं अपने अधिकारों के प्रति सजग रहकर विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय योगदान देना चाहिए। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. एसबी कुमार ने की। उन्होंने स्वागत भाषण में संकाय विकास कार्यक्रम के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए महिला सशक्तिकरण से संबंधित विभिन्न शासकीय योजनाओं का उल्लेख किया तथा वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक में भारत की स्थिति पर चिंता व्यक्त की। प्रथम दिवस की मुख्य वक्ता डॉ. आराधना शुक्ला सहायक प्राध्यापक (रायपुर) ने महिलाएं एवं वित्तीय नेतृत्वः आर्थिक नीति निर्माण में उनकी भागीदारी एवं सशक्तिकरण विषय पर व्याख्यान दिया। उन्होंने कहा कि वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी से लगभग 20 प्रतिशत तक वृद्धि संभव है तथा भारतीय कृषि क्षेत्र में महिलाओं का योगदान 70 प्रतिशत से अधिक है। आमंत्रित वक्ता डॉ. निधि सिंह शुक्ला ने सशक्त भारत के निर्माण में महिलाओं के योगदान, नेतृत्व क्षमता एवं अदम्य साहस का उल्लेख किया, महिला सशक्तिकरण और टेक्नोलॉजी व योजनाओं का उल्लेख किया। कार्यक्रम का संचालन डॉ. स्वेतलाना नागल द्वारा किया गया।

यह कार्यक्रम महाविद्यालय के संरक्षक डॉ. शीलभद्र कुमार, प्रभारी प्राचार्य एवं संयोजक डॉ. सरस्वती वर्मा (विभागाध्यक्ष, हिंदी) तथा समन्वयक डॉ. स्वेतलाना नागल (विभागाध्यक्ष, सूक्ष्मजीव विज्ञान) के मार्गदर्शन में आयोजित किया जा रहा है। आयोजन टीम में ओमप्रकाश पटेल (विभागाध्यक्ष, भूगोल), डॉ. मनोज कुमार शर्मा (विभागाध्यक्ष, वाणिज्य), अजय कुमार श्रीवास (पुस्तकालयाध्यक्ष) सहित प्राध्यापकगण ओंकार साहू, जगदीश प्रसाद खटकर, वंदना यादव, अरविंद साहू, कविता गहीर, खगेश्वर नवरंगे, अतिथि व्याख्यातागढ़ एवं महाविद्यालय स्टाफ गुप्तेश नामदेव, उमा साहू, डॉ.लोकनाथ तारक, डॉ चित्रलेखा साहू, डॉ हेमेंद्र साहू, डॉ संजय कुमार वर्मा, दूलामणि रौतिया, प्रेरणा कॉपसे, पूजा साहू, चमन आडिले, संतराम मन्नाडे, रामकृष्ण साहू, अश्वनी कुमार लोधी, अहिल्या लहरे, मनीष बंजारे, विनोद बंजारे, कामीन लहरे का योगदान रहा।

जिलों में भ्रमण कर पिछड़ा वर्ग के लोगों से लिया जा रहा सुझाव

हरिभूमि न्यूज ⏭ जगदलपुर

पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन जनसंख्या के आधार पर रिजर्वेशन एवं भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया है। आयोग द्वारा सबसे पहले सर्वे करवाया और पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या को स्पष्ट किया गया। इसके बाद से प्रत्येक जिले में भ्रमण कर वहां के पिछड़ा वर्ग के लोगों से चर्चा कर सुझाव लिया जा रहा है। रिपोर्ट में बेहतर सुझाव को शामिल किया जा रहा है।

उक्त बातें पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष आरएस विश्वकर्मा ने मंगलवार को शहर के सर्किट हाऊस में पत्रवार्ता में कही। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में पिछड़ा वर्ग समाज में 95 जाति के लोग शामिल हैं। इन समाज के लोगों की सरकारी योजनाओं में कितनी भागीदारी है और समाज के लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं इसकी जानकारी ली जा रही है।

एक वर्ष पूरे होने पर श्रमदान से बनाया क्रिकेट मैदान

हरिभूमि न्यूज ⏭ झलप

ग्राम लखनपुर पंचायत के एक वर्ष पूरे होने पर सरपंच, उपसरपंच, समस्त पंच एवं युवा ग्रामीणों ने क्रिकेट मैदान निर्माण के लिए श्रमदान किया।

सभी के आर्थिक सहयोग का योगदान किया, जिससे मिट्टी मुरम डाली गई। जेसीबी मशीन लगाकर मैदान को समतल किया। जिसके उद्घाटन में मुख्य अतिथि जिला महामंत्री भाजपा ओबीसी मोर्चा निर्भय नायक उपस्थित रहे। सरपंच खेमिन चोवाराम ध्रुव, उपसरपंच महामंत्री भाजपा झलप मण्डल कमल कौशिक, सरपंच प्रतिनिधि चोवाराम ध्रुव के साथ में युवा ग्रामीण वेदप्रकाश पटेल, डॉ सीतेश पटेल, सतीश जोशी, देवदत्त साहू, भूपेंद्र यादव, बलराम जोशी, भूखन जोशी, प्रेम सागर जोशी, पवन साहू, गिरजा शंकर जोशी, भानू जोशी, कौशल साहू, यादराम ढीवर, तमेश्वर जोशी, हेमेंद्र जोशी, खिलेश्वर जोशी, लाला जोशी, शिवम जोशी, नरेश यादव, रवि जोशी, गुलशन यादव, दुर्गेश यादव, वीरू यादव, लारेंस जोशी, टिकेश यादव आदि उपस्थित रहे।